मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 15
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 11 जुलाई 2025 Rs. 10/-

पीएम जनमन योजना और जशप्योर बना जशपुर की पहचान

छत्तीसगढ़ का जशप्योर बना अंतरराष्ट्रीय ब्रांड

पर्यटन के क्षेत्र में उभरता जशपुर

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंद्रा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

जशपुर विशेषांक

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 25 अंक 11 जुलाई 2025

(पृष्ठ क्र.-6)

- हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 42
- कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी ? 44
- अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जिस एलन मस्क ने ट्रंप की मदद की 52
- कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, इजराइल और यूक्रेन के बीच 55
- ईरान-इजरायल के बीच युद्ध विराम 58
- Laxman Yadav: 'Manusmriti' could only be taught 62

इन दोनों में से कोई भी बनता है
तो समझो हमारी सरकार रिपीट है!
विजय:)

विश्व पटल पर उथल-पुथल, युद्धों ने बढ़ाई चिंता

वर्तमान में विश्व पटल पर काफी उथल-पुथल मची हुई है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान युद्धों ने विश्व की चिंता बढ़ा दी है। युद्ध भले ही इन देशों के बीच चल रहा हो लेकिन इसके परिणाम विश्व के अधिकांश देशों को भोगने पड़ सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जिस एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था की कल्पना की गई थी, वह अब बहुध्रुवीय होती जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसी महाशक्तियां अपनी शक्ति के नए समीकरण बना रही हैं। कई क्षेत्रीय शक्तियां भी उभरकर वैश्विक मंच पर अपने हितों को मुखर कर रही हैं। इसी शक्ति संघर्ष ने दुनिया के कई हिस्सों को राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और संघर्ष की आग में झोंक दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है जिसने यूरोप की स्थिरता को सीधा चुनौती दी है। 2022 में शुरू हुए इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उर्जा संकट, अनाज संकट और शरणार्थी समस्या ने कई देशों के आंतरिक राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका और नाटो का सीधा हस्तक्षेप, रूस की जिद और यूक्रेन का प्रतिरोध इस संघर्ष को लंबे समय तक खींच रहा है। एशिया में चीन लगातार आक्रामक रवैया अपना रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसका वर्चस्व बढ़ाना, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से टकराव, भारत के साथ सीमा विवाद और बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से छोटे देशों को ऋणजाल में फंसाना- ये सभी उसकी विस्तारवादी नीतियों के प्रमाण हैं। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश क्वाड के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य पूर्व की राजनीति भी अशांत है। इजराइल और हमास के बीच हालिया युद्ध ने दुनिया को फिर से यह याद दिला दिया कि यह क्षेत्र स्थायी शांति से कोसों दूर है। ईरान और सउदी अरब के बीच सत्ता संतुलन, सीरिया और यमन के गृहयुद्ध, आतंकवाद और धर्म के आधार पर फैलाई जा रही कट्टरता ने इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाए रखा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा इराक और सीरिया में की गई सैन्य कार्रवाइयाँ और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों की चिंता, इस इलाके में उथल-पुथल को और जटिल बना रही हैं।

अफ्रीका में भी कई देशों में सत्ता संघर्ष देखने को मिल रहा है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है। पश्चिम अफ्रीका में नाइजर, माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में सैन्य तख्तापलट ने लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाई है। दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन अब भी सहारा और साहेल क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिससे विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां की अस्थिर सरकार, सेना और न्यायपालिका के बीच टकराव, आतंकवाद का फिर से सिर उठाना- ये सब इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए चिंता का विषय हैं।

यूरोप में भी उथल-पुथल जारी है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन आंतरिक असंतोष, आर्थिक दबाव और अलगाववादी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है। फ्रांस और जर्मनी में दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिससे यूरोपीय एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारी घटनाओं का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। उर्जा संकट, खाद्यान्न संकट, महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की समस्या ने दुनिया के कई देशों में जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। विश्व राजनीति में बदलाव की यह लहर बताती है कि शक्ति संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता। तकनीक, पर्यावरण और आर्थिक हितों ने इसे और जटिल बना दिया है। ऐसे में समझदारी, कूटनीति और सहयोग ही स्थायी शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि नेता अपने राष्ट्रहित से उपर उठकर वैश्विक मानवता का हित सोचें। तभी यह उथल-पुथल थमेगी और एक नई स्थिर विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा।

विजया पाठक

पीएम जनमन योजना और
जशप्योर बना जशपुर की पहचान
छत्तीसगढ़ का जशप्योर बना अंतरराष्ट्रीय ब्रांड
पर्यटन के क्षेत्र में
उभरता जशपुर
Mahua

छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला झारखंड और ओडिशा की सीमा के निकट भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित है। जशपुर घने जंगल और हरी वनस्पतियों से समृद्ध है। जिले के उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ियों और पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला होती है, कभी-कभी एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं या कहीं-कहीं क्रिस-क्रॉसिंग होती है। हरे-भरे इलाके और घाटियों में सुरूचिपूर्ण प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है। यह पूर्णतः आदिवासी जिला है और यहां ऐसी कई जनजातियां निवास करती हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। एक समय था जब जशपुर अति पिछड़ा एवं मुख्य धारा से कटा हुआ जिला कहलाता था लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब जशपुर की पहचान विश्व पटल पर पहुंच चुकी है। जशपुर की इस प्रसिद्धि के पीछे पीएम जनमन योजना और जशप्योर ब्रांड को माना जा रहा है। इन दोनों योजनाओं ने इस जिले की काया पलट करके रख दी। यहां के लोग उन्नत खेती-किसानी कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला कभी सिर्फ अपने जंगल और महुआ के लिए ही जाना जाता था। लेकिन अपनी हरी-भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये गृह जिला अब एक नई पहचान बना रहा है। पूरे देश और दुनिया में जशपुर से निकले जशप्योर ब्रांड की खुशबू फैल रही है। जशप्योर ब्रांड आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और आर्गनिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास में अनवरत कार्य कर रहा है। अब यह ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफ लाइन। सारा कुछ संभव हुआ है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन और तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल की मेहनत से। जिन्होंने जशप्योर के उत्पादों को ब्रांड बनाने के लिए अथक प्रयास किये और अंततः उसमें सफल भी हुए। जबसे विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली है, जशपुर जिला हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। यहां की महिलाएं भी कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। साथ ही पीएम जनमन योजना भारत में आदिवासी समुदायों की सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को संबोधित करने वाले अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ, यह पहल समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे यह योजना लोगों तक पहुंच रही है, वैसे-वैसे वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक उज्जवल और भविष्य का वादा करती हैं, जो अधिक समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किए गए प्रयासों से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज मुख्यतः पहाड़ी कोरवा समुदाय में एक नई रोशनी आई है। यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि विकास के उन सपनों को साकार करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो अब तक अधूरे थे। योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। यह योजना जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विजया पाठक

आज हम पत्रिका की इस कवर स्टोरी में केवल छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बात कर रहे हैं। पहले भले ही यह जिला अविकसित और पिछड़ा था, लेकिन अब यह जिला विकास की नई इबारत लिख रहा है। खासकर पीएम जनमन आवास योजना तथा जशप्योर ब्रांड के कारण जशपुर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। लोग स्वावलंबी होकर बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जशपुर की आदिवासी महिला से जशप्योर ब्रांड के विषय में बातचीत की। पीएम मोदी ने पीएम जनमन योजना सहित अन्य विषयों पर खुलकर बात की। आदिवासी महिला ने भी अपने मन की बात करते हुए शासकीय योजनाओं के विषय में जानकारी दी।

पीएम जनमन योजना

शासन की योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाती है जब उनकी पहुंच और क्रियान्वयन समाज के सबसे निचले तबके तक सुनिश्चित हो। प्रदेश में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों अभी भी शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। अपनी लोक संस्कृति और पारम्परिक विरासत एवं मूल्यों के साथ जीवन-यापन करने वाली यह जनजातियां कई मायनों में आज भी पिछड़ी हुई हैं। पीएम जनमन योजना का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति को सशक्त बनाने के विजन की दिशा में कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए किया

लोगों को मिल रहा, शासकीय योजनाओं का लाभ

पहाड़ी कोरवा जनजाति का हो रहा विकास

जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाभार्थियों को पीएम जनमन आवास योजना के तहत आवंटित मकानों की चाबी सौंपते हुए। जिले में हजारों लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिनको अभी तक मकान नही मिला है उनको भी मिलने वाला है।

गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सभी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जन-धन बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम मातृत्व वंदन योजना और राशन कार्ड जैसी आवश्यक सेवाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा और बैगा जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र-पुत्रियां कहा जाता है लेकिन आजादी के कई साल बाद तक भी इनकी बस्तियों में शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं था। घास-

4000 से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराकर सौंपी गई चाबी

जशपुर जिले में कई लोगों को पक्के मकान के सपने साकार हो रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवासरत लोगों की आशायें पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निरंतर प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 4322 ग्रामीणों को पक्का आवास मिला है। इन आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात् हितग्राहियों के गृह प्रवेश और उनके चाबी सौंपने के लिए राज्यव्यापी गृह प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को उनके नए नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के सपनों को साकार करने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मकान बनाने की चिंता को भी दूर कर रहा है। जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा के 70 साल के संतु चक्रेस अपना खुद का पक्का मकान पाकर खुश हैं और उनकी खुशी दुगनी हो गई जब मुख्यमंत्री जशपुर प्रवास पर थे और उनके हाथों से घर की चाबी मिली।

फूस के घरों में बिजली कहां से पहुंच पाती और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं तो इनके लिए लक्जरी ही समझिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिस्थिति को पूरी संवेदनशीलता से समझा और उन्हें लगा कि इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए मामूली प्रयत्नों से कुछ नहीं होगा, जब तक एक लक्ष्योन्मुखी वृहद योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए नहीं बनेगी तब तक इनके कल्याण की सूरत नहीं बनेगी। फिर पीएम जनमन योजना लायी गई और इस योजना से निकली उजाले की किरण इन बस्तियों में

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पण्ड्रापाट के बुचू राम का सपना हुआ पूरा

हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो। जिसे पूरा करने के लिए वह जीवन भर मेहनत करता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए स्वयं का पक्का आवास बना पाना एक सपने जैसा होता है उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत गरीब लोगों को स्वयं का आवास बनवाने के सपने को साकार कर रही है। राज्य में योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जशपुर जिले में पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जनमन आवास और पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। बगीचा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पण्ड्रापाठ के बुचू राम के पास अपना पुश्तैनी कच्चा आवास था। जिसमें वह अपनी पत्नि और बच्चों के साथ मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था और बरसात के मौसम में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में पक्का आवास बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि से अपना पक्का मकान बनाकर अब वह अपने बच्चों के साथ सुकून से रह रहे हैं। बुचू राम ने बताया कि मेरा कच्ची दीवार वाला पुराना घर था, जिसके उपर पन्नी तान कर गुजर-बसर चल रहा था बरसात के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती थी तो मेरे घर के चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण घर बनवाने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी।

फैल चुकी है। पक्के घरों में बिजली पहुंच रही है। बच्चों के लिए स्कूल खोले गये हैं और इन तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बनाई जा रही हैं। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों के रहवासी इलाकों में विकास का उजियारा साफ-साफ दिखाई देने लगा है। इस उजियारे से जनजातीय समुदाय के लोगों में शासन के प्रति एक नया विश्वास जागा है और उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई देने लगी है। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के बीच विकास,

क्या है पीएम जनमन योजना?

पीएम जनमन योजना को मिशन के तौर पर छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के परिवारों के लिए चलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया। इस स्कीम के तहत कई रूपों में काम किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है। इसके तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना में 09 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे पक्का आवास, विद्युतीकरण, सड़क, पेयजल जैसी सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समुदाय के लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने और

पीएम जनमन अवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी

उनके रहवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। शासन की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के चलते छत्तीसगढ़ के

मैंने देखा एक सपना, सुंदर घर हो अपना

जशपुर जिले के जनपद पंचायत मनोरा के ग्राम पंचायत करदना (छतौरी) से है, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा जो ज्यादातर घने जंगलो में पेड़, पत्ते एवं छाल से झोपड़ी बनाकर निवास करते थे जिन्हें बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष टपकते छत एवं सांप-बिच्छू की समस्या रहती थी। जिसके कारण उन्हें जीवन-यापन करना एक चुनौती थी। ऐसे में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना एक वरदान साबित हुई है। इन सभी हितग्राहियों को शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने एवं मुख्यधारा से जोड़ने हेतु एक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थापन कर एक सुविधायुक्त कॉलोनी का निर्माण किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में पीएम जनमन आवास का निर्माण किया जा रहा है एवं कॉलोनी में समस्त पहाड़ी कोरवा परिवारों हेतु व्यक्तिगत शौचालय, जीवन यापन हेतु सभी परिवारों को मुर्गी/बकरी शेड की स्वीकृति दी जा रही है। मुख्य मार्ग से कॉलोनी तक पहुंचने के सीसी रोड़ की स्वीकृति एवं कॉलोनी में सोलर स्ट्रीट लाईट, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है।

जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर और उनके रहवासी क्षेत्रों में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा है। योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान की स्वीकृति एवं निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां और इसके 161 उपजातियां हैं। इस वर्ग में बिंझवार, सावरा, गोंड, मुरिया, हलबा, भतरा, भुंजिया, भूमिया (भूइया), बियार, कंवर, मझवार, माझी, मुण्डा, भैना,

ये हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति आदिवासी समाज के लोगो के अपने पुराने मकान। इन्हीं मकानों में रहकर यह समाज अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार इन मकानों की जगह नये पक्के मकान बना कर दे रही है। पीएम जनमन आवास योजना के तहत जिले में सबको इस योजना का लाभ मिल रहा है।

नगेसिया आदि विभिन्न जनजातियां आती हैं। इस वर्ग की जनजातियां जंगली उपज संग्रह, शिकार, आदिम कृषि के साथ-साथ बांस से टोकरी आदि बनाते हैं। इस समूह में कमार, कंडरा, धनवार, सोता, बैगा, माझी आदि आते हैं।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए पांच जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जिसमें बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़ियां जनजाति आती हैं। छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 3,10,625 है। इनमें से पहाड़ी कोरवा जनजाति की कुल जनसंख्या 1,29,429 है। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा, और रायगढ़ ज़िलों में पाई जाती हैं। पहाड़ी कोरवा प्राचीन समय में बेबर कृषि करते थे अर्थात जंगल में आग लगाकर ज़मीन साफ़ करते थे तथा बरसात के समय बीज छिड़क देते थे। पहाड़ी कोरवा स्त्री-पुरूष दैनिक मजदूरी हेतु ग्राम के अन्य जनजातियों के यहाँ कार्य करते हैं। ये मुख्यतः कृषि-मजदूरी एवं गड्ढे खोदने हेतु मजदूरी का कार्य करते हैं।

जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम जनमन आवास योजना के तहत इस तरह के पक्के आवास बनाकर दिये जा रहे हैं। इन मकानों में जरूरत की सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन आवासों में रहकर लोगों की जिंदगी बदल रही है। पीढ़ियों से रह रहे कच्चे मकानों से अब इन्हें छुटकारा मिल गया है।

इसी प्रकार बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। सर्वेक्षण अनुसार इनकी साक्षरता प्रतिशत 53.97 है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कवर्धा और बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय वनोपज संग्रह, पशुपालन, खेती तथा ओझा का कार्य करना है। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय बांस से टोकरी, झांपी, पर्रा वगैरह बनाना है। इसके अलावा, पक्षियों और छोटे जानवरों का शिकार करना भी इनका जीविकोपार्जन का साधन है। कमार जनजाति के लोग आपसी संवाद के लिए कमारी बोली और स्थानीय रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देश में उनकी अधिकांश आबादी झारखंड से सटे हुए सीमावर्ती जिलों में रहती है। अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में है। जिसके कारण इन्हें

साय सरकार में हो रहा पहाड़ी कोरवा जनजाति का विकास

रोटी, कपड़ा और मकान- जीवन की तीन सबसे आम आवश्यकता हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हर व्यक्ति लगातार प्रयास करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आजीविका के सीमित संसाधन होते हैं। लोग अपने परिवार की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि इन्हें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता मिल जाए तो जीवन के बड़े परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने ऐसे ही परिवारों के घर के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जशपुर जिले में अधिकतर पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक समय था जब इस जनजाति के लोग विकास की मुख्यधारा से कटे थे। लेकिन अब स्थितियां इसके उलट हैं। जबसे प्रदेश में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं तबसे इस जनजाति की जिंदगी बदल गई है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। राशन कार्ड से अनाज मिलने लगा है। इन लोगों को पीएम जनमन योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। अधिकतर लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और मिल रहा है। जगत विजन की टीम ने जशपुर जिले के कई गांवों में जाकर पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों से बातचीत की। और उनकी समस्याओं के विषय में जाना। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश-

जगत विज़न पत्रिका की टीम ने जशपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में जाकर पहाड़ी कोरवा जनजाति व अन्य जनजाति के लोगों से बातचीत की है। उनके मन की बातें जानी हैं और सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के विषय में जाना है। सभी लोगों ने सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लिए मौजूदा साय सरकार की तारीफ की है। लोगों का कहना था कि अब हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहा है।

स्थानीय बोली में अबूझमाड़िया कहा जाता है।

पीएम जनमन पहल ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कई प्रभावशाली गतिविधियाँ शुरू की हैं। कार्यक्रम ने PVTG समुदाय के लिए कुल 30 हजार से अधिक घरों को मंज़ूरी दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन

मुख्यमंत्री ने हमारी सुध-बुध ली है

मैं पहाड़ी कोरवा जाति से हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारा घर बनवाकर दे रहे हैं। पीएम जनमन आवास योजना में मुझे घर बनाने के लिए 2 लाख रूपये मिले हैं। अनाज भी मिलता है। मेरा दो कमरे का पक्का मकान बनेगा। अब मेरे बच्चे बरसात में गीले नहीं होंगे। मेरे परिवार में 7 लोग हैं। पांच बच्चे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल मेरे से घर से नजदीक है। पांचवी के बाद बच्चों को सन्ना गांव में पढ़ाई के लिए भेजूंगा। मैं घर का खर्च का चलाने के लिए मिर्ची के खेत में मजदूरी करने जाता हूं। मुख्यमंत्री ने हमारी सुध-बुध ली है। अब हमारा जीवन भी अच्छा बन जायेगा।

चूट्टू, (पहाड़ी कोरवा) लेदरापाट गांव, जनपद सन्ना, जिला जशपुर

परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आश्रय मिल सके। बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को समझते हुए, 1,044.78 करोड़ रूपए के बजट के साथ 398 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में, इनमें से 328 सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो आदिवासी समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं और बाजारों तक पहुँच को बढ़ाएँगी। बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने

सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है

जनमन योजना में हमें भी पक्का मकान मिलने वाला है। सरकार ने हमें आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाकर दिये हैं। राशन कार्ड से मुफ्त में चावल मिलता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी सरकारी स्कूलों में करवाई जा रही है। गांव के अंदर तक पक्की सड़क बन गई है। अब आने जाने में कोई परेशानी नही है। इसके अलावा सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड से हमें मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं।

झीपनी बाई (पहाड़ी कोरवा), लेदरापाट, सन्ना जनपद, जिला जशपुर

हमारी जिंदगी में बदलाव आया है

पीएम जनमन योजना में मकान मिलने वाला है। वर्तमान में हम अपने कच्चे मकान में रह रहे हैं। लेकिन जल्द ही पक्के मकान में रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण हमें सब प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। सभी सरकारी कागज भी बन गये हैं जिससे हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड के बनने से राशन मिलने लगा है। साथ ही बच्चों को भी सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया है। नई सरकार के आने से हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। पहाड़ी कोरवा की जनजाति के लोगों को अब सुध ली जा रही है।

मंगरी बाई (पहाड़ी कोरवा), लेदरापाट, सन्ना जनपद, जिला जशपुर

पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगो के बीच जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

के लिए, 7,067 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत, 17,372 घरों में पाइप से जलापूर्ति शुरूकी गई है, जबकि 9,473 और घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ पेयजल तक यह पहुँच स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए, 57 मोबाइल मेडिकल इकाइयों को मंजूरी दी गई

मिल रहा शासकीय सुविधाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार हमारी काफी मदद रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे गांव के पास बगीचा के हैं। जब भी उनका इस क्षेत्र में आना होता है वह हमारे गांव में भी आते हैं। हमारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। कोइ भी परेशानी होती है तो तुरंत निपटा देते हैं। नई सरकार के आने से हमें कोई परेशानी नही हो रही है। हमारे गांव का भी विकास हो रहा है। सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। राशन मिलने लगा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

पहरूराम, पहाड़ी कोरवा,
पेण्ड्रापाट गांव

खुशी है कि मुख्यमंत्री हमारी सुध ले रहे हैं

हमारे गांव में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। गांव में कुल 211 परिवार रहते हैं। जिनमें 131 जनमन योजना के तहत पक्के मकान बने हैं। बाकि मकान भी बन रहे हैं। हमारे पास जमीन है। हम लोग भी खेती किसानी करते हैं। इसकी उपज से परिवार का भरण पोषण करते हैं। नई सरकार भी हमारी काफी मदद कर रही है। सभी सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री भी हमारी जनजाति के लिए विशेष काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि कोई मुख्यमंत्री हमारी सुध ले रहे हैं। हमारे गांव का विकास भी हो रहा है। साथ ही हम लोग अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।

फुल्लो बाई, पेण्ड्रापाट

पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगो के बीच जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

है, जिनकी परिचालन लागत 33.88 लाख रूपए प्रति इकाई है। ये इकाइयाँ दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं।

पीएम जनमन योजना भारत में आदिवासी समुदायों की सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को संबोधित करने वाले अपने व्यापक

पीएम जनमन योजना में मिला पक्का मकान

जशपुर जिले के विकासखंड मनोरा के ग्राम पंचायत करदना में इस योजना के तहत मिले आर्थिक सहयोग से कई परिवारों के जीवन में रोशनी आई है। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान योजना के तहत जिले के सुदूर क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग झोपड़ी बनाकर निवास करते थे, जिन्हें बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष बारिश टपकता था। सांप बिच्छू की समस्या बनी रहती थी। हर साल छत की मरम्मत करने में खर्च होती थी। लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना मेरे लिए वरदान साबित हुई, जिसके तहत पहाड़ी के नीचे बस्ती छतौरी में पीएम जनमन आवास योजना के तहत पक्का आवास के साथ शौचालय बनाकर तैयार है। इसी तरह इनका खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है। मेरे दादा पहाड़ी के उपर गुफा में निवास करते थे और पिताजी नीचे पहाड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। लेकिन अब पक्का आवास मिलने से यह परेशानी खत्म हो गई है।

जगतपाल राम, ग्राम छतौरी, जनपद पंचायत, मनोरा, जिला जशपुर

दृष्टिकोण के साथ, यह पहल समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे यह योजना लोगों तक पहुंच रही है, वैसे-वैसे वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का वादा करती हैं, जो अधिक समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री

गांव को विकास की धारा में लाना है

मैं लेदरापाट पंचायत का सरपंच हूं। चादूँपाट भी इसी पंचायत में आता है। हमारे गांव में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। हम गांव में पहाड़ी कोरवा समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास बनवा रहे हैं। अब पहाड़ी कोरवा समुदाय के गांव और बसाहट तक रोड पहुंचाना है। आंगनवाडी का निर्माण कराया जा रहा है ताकि पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चों का विकास कम उम्र से हो सके। साथ ही गांव के विकास के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। गांव के अंदर सरकार के सहयोग से कई विकास कार्य हो रहे हैं। जो हमारे समुदाय के लाभदायक है।

अरविंद कुजूर, सरंपच, जनपद सन्ना

पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगो के बीच जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक एवं कार्यकारी संपादक समता पाठक

जनमन योजना के तहत किए गए प्रयासों से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में एक नई रोशनी आई है। यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि विकास के उन सपनों को साकार करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो अब तक अधूरे थे। योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बुनियादी

जगत विज़न पत्रिका की संपादक विजया पाठक ने सन्ना पंचायत की स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। इन महिलाओं ने अपने रोज़गार और व्यवसाय के विषय में बताया कि कैसे यह आत्मनिर्भर हुई हैं।

सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। यह योजना जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जशपुर जिला बना पर्यटन का नया स्थान

छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर बसा जशपुर एक ऐसा जिला है जहाँ की अनुपम छटा, जनजातीय संस्कृति की गहराई और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहां का जलप्रपात, चाय बागान, पौराणिक मंदिर और लोकजीवन इसकी समृद्ध विरासत का साक्षी है। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला सुंदर वादियों और नदी पहाड़ झरना से परिपूर्ण खूबसूरत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। अब जिला तेजी से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहां के घने जंगल, पर्वतीय क्षेत्र और अनोखी आदिवासी संस्कृति ने जशपुर को एक विशेष पहचान दिलाई है। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। उनका उद्देश्य एक ऐसा पर्यटन मॉडल तैयार करना है, जो न केवल पर्यटकों के लिए रोमांचक हो, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखे पर्यटन को प्रकृति

जशपुर में पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगों की बस्ती

के करीब पहुंचाने का प्रयास किया है। प्राकृतिक संपदा जैसे घने जंगलों, पहाड़ियों और जल संसाधनों को भी पर्यटकों के अनुभव का हिस्सा बनाया है, जिससे न केवल पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव मिलता है, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी रोजगार मिलता है। जशपुर की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के करीब लाना है।

पीएम जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान) के चलते छत्तीसगढ़ राज्य अति पिछड़े जनजातीय समुदाय तकदीर और इनकी बसाहटों की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के रहवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होने लगा है। बरसों-बरस से आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन जनजातीय समूहों को अब मिशन मोड में यह बुनियादी सुविधाएं सुभल होने लगी है।

पीएम जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान) के चलते छत्तीसगढ़ राज्य अति पिछड़े जनजातीय समुदाय तकदीर और इनकी बसाहटों की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है।

छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लोग निवास करते हैं। जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से बैगा, छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति समुदाय है। छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त 05 जिलों में बैगा समुदाय के 24 हजार 589 परिवार निवासरत है, जिसमें से लगभग 46 प्रतिशत यानि 11 हजार 261 परिवार कबीरधाम जिले में रहते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेती-किसानी के लिए दी जा रही मदद के चलते अब बैगा समुदाय के लोग बेवर खेती को छोड़ परंपरागत तौर-तरीकों से खेती-किसानी करने लगे हैं। बेवर खेती दरअसल झूम खेती है। बैगा समुदाय के लोग एक स्थान पर स्थायी तौर पर निवास न करने के कारण बेवर यानी झूम खेती किया करते थे। बिना ब्याज के कृषि ऋण, अनुदान पर कृषि यंत्रों सहित अन्य सुविधाएं मिलने की वजह से बैगा समुदाय के लोग अब बेवर खेती को छोड़ स्थायी खेती करने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी की स्थिति

साल 2015-16 के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 05 प्रकार की जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। इनमें अबूझमाड़ी, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा जनजाति शामिल हैं।

अबूझमाड़ी जनजातिः अबूझमाड़ी जनजाति नारायणपुर जिले के 02 ब्लॉक के 249 गांवों में बसते है। अबूझमाड़ी जनजाति के कुल 23,330 लोग यहां रहते हैं। जिनके परिवारों की संख्या 4786 है।

बैगा जनजातिः बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली और राजनांदगांव जिले में निवास करते हैं। इनके परिवारों की संख्या 24,589 है। इनकी कुल 88 हजार से ज्यादा जनसंख्या यहां निकास करती है।

बिरहोर जनजातिः पीवीटीजी में शामिल बिरहोर जनजाति की अधिकांश जनसंख्या बिलासपुर, जशपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में कुल 304 परिवारों के 958 लोग निवास करते हैं।

कमार जनजातिः विशेष संरक्षित जनजाति में कमार जनजाति भी शामिल हैं। ये बलौदाबाजार, धमतरी गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव और महासमुंद जिले में निवास करते हैं। कुल 7474 कमार परिवार हैं। कमार जनजाति के लोगों की इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या 26,622 है।

पहाड़ी कोरवा जनजातिः छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बलरामपुर, जशपुर, कोरबा और सरगुजा जिलों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन क्षेत्रों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के कुल 11,235 परिवार हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 44,026 है।

पीवीटीजी वर्ग के लिए पीएम जनमन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। योजना के तहत शासकीय विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण,

वनधन केंद्र की स्थापना, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पक्का आवास, नल जल योजना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान-पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विभिन्न

सभी को बुनियादी सुविधाओं का मिल रहा लाभ

देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। योजना के क्रियान्वयन से जशपुर जिले में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरूहो

देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उनकी आशाओं पर लगातार खरे उतर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के बीच भी वे अपने गृहग्राम जशपुर जिले के ग्राम बगिया में समय निकालकर आते रहते हैं। वे रायपुर स्थित अपने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री साय ने बगिया में भी मुख्यमंत्री

योजनाओं का लाभ देने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन परिवारों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन इन समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने लगातार प्रायसतर है जिसका अब सुखद और सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की लाभ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को देने के उद्देश्य से योजना के तहत जिले के जनजातीय क्षेत्रों में शिविर आयोजन का सिलसिला जारी है।

गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति समुदाय लोग अब अपने परिवार के साथ एक सुन्दर से पक्के घर में रह रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना के विकास के लिए एक रोडमैप बनाकर लगातार कार्य किया जा रहा है। जशपुर जिले के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था विष्णु देव साय का मुख्यमंत्री बनना। इससे यहां के लोगों के चेहरे में एक चमक आने के साथ उनसे उम्मीद भी बढ़ गई। लोग उन्हें अपने सपनों को साकार करने वाले नायक के रूप में भी

कैंप कार्यालय की स्थापना की है। यहां पर जशपुर जिले के अलावा प्रदेश भर से पूरी आशा के साथ लोग आ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी या अन्य समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया भी जा रहा है। जशपुर जिले के लगभग 250 ग्राम पंचायत हाथी विचरण क्षेत्र है। कैंप कार्यालय का लक्ष्य इन हाथी प्रभावित इलाके में विद्युत व्यवस्था को और भी दुरूस्त करने की है। जानकारों की माने तो रोशनी होने पर हाथियों की बस्ती में घुसपैठ होने आशंका कम रहती है।

दुनिया भर में बिखर रही जशप्योर ब्रांड की खुशबू

छत्तीसगढ़ जिसे धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, वही छत्तीसगढ़ अब जशपुर ब्रांड के नाम से पहचान बना रहा है। जशप्योर ब्रांड आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। अब यह ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सारा कुछ संभव हुआ है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन और मेहनत से। जब से विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली है, जशपुर जिला हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। यहां की महिलाएं भी कामयाबी की नई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले से हैं। यही कारण है कि इस जिले से उनका खास लगाव है। जिले के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री बनते ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जिले की जनता भी मुख्यमंत्री से काफी उम्मीद रखती है और उन उम्मीदों पर वह खरे भी उत्तर रहे हैं।

इबारत लिख रही हैं। जशप्योर ब्रांड आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। इसी का एक बेहतर उदाहरण और उत्कृष्टता का प्रतीक है। जशप्योर ब्रांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद ढेकी कुटा जवा फूल चावल, जो कि अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए। इस चावल की सुगंध और स्वाद अनूठा है। वही महुआ और मिलेट लड्डू से बने लड्डू पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। यह लड्डू विशेष रूप से बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। इसी तरह मिलेट आधारित पास्ता, यह पास्ता पारंपरिक गेहूं के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों

जशप्योर ब्रांड की मुंबई, पुणे से लेकर एमपी के शहरों में बढ़ी डिमांड

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। जशप्योर ब्रांड की मुंबई, पुणे से लेकर एमपी के शहरों में बढ़ी डिमांड बढ़ी है। जशप्योर ब्रांड के माध्यम से स्थानीय आदिवासी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के तैयार किए गए उत्पादों की कैसर पुणे में जशपुर की पहल पर जशप्योर ब्रांड के उत्पादों की पुणे के विभिन्न स्थानों पर नियमित स्टॉल लगाई जा रही हैं। जहां जशपुर जिले के स्थानीय कच्चे माल से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये उत्पाद अपनी शुद्धता और स्वास्थ्य लाभ के कारण उच्च मांग में हैं, क्योंकि इनमें कोई रसायन नहीं होते हैं, जिससे वे बाजार के अन्य उत्पादों की के लिए एक उत्तम विकल्प है। इनके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाउ एवं महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। जशप्योर के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक, जशप्योर के उत्पादों को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक गुण के साथ शुद्धता, जिसने हर किसी को जशप्योर ब्रांड का आदी बना दिया है।

तुलना में एक स्वस्थ विकल्प बन जाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जशपुर के आदिवासियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने में जिला प्रशासन का प्रयास सराहनीय हैं। यह पहल न केवल आदिवासी समुदायों को सशक्त बना रही है बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी सुनिश्चित कर रही है। स्थानीय आदिवासी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पादों को मुम्बई में भी पसंद किया जा रहा है। मुंबई में लगी प्रदर्शनी का लोगों ने अवलोकन करके बड़ी मात्रा में खरीदी भी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर तत्कालीन जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जशप्योर ब्रांड का मुंबई के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाई गई थी। जहां जशपुर जिले के स्थानीय कच्चे माल से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। जशपुर की आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अपनी शुद्धता और स्वास्थ्य लाभ के कारण उच्च मांग में हैं, क्योंकि इनमें कोई रसायन नहीं होते हैं, जिससे वे बाजार के अन्य उत्पादों की तुलना में स्वस्थ विकल्प बन जाती हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से जशपुर जिले के आदिवासियों के साथ-साथ जवाहर जिले के आदिवासियों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

वर्ल्ड फूड इंडिया में जशप्योर उत्पादों को लोगों ने लिया हाथों-हाथ, बढ़ रही है मांग

जशप्योर उत्पाद को बड़े शहरों में भी लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं और इनकी मांग निरंतर बनी हुई है। ओयो कंपनी के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने जशप्योर ब्रांड की सराहना करते हुए कहा कि, जशपुर से ब्रांड निकला जशप्योर, मुझे लगता है देश भर में एक प्रोडक्ट विशाल बनेगा और इसको देखकर और लोग भी प्रोत्साहित होंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में जशप्योर का स्टॉल दिल्ली सहित मुम्बई, मध्यप्रदेश के रीवा, बिहार, राजस्थान आदि बड़े महत्वपूर्ण शहरों में लगाया गया था। जशप्योर बांड विशेष रूप से पोषण के प्रति उत्साही और स्वस्थ जीवन शैली बनाने वालों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

यहां का जशप्योर ब्रांड अब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है। जशपुर ब्रांड के अंतर्गत कई प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। जिनमें सबसे ज्यादा मांग वाले प्रोडक्ट ढेकी, कुटा, जवा फूल चावल है, जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। महिला समूहों की ओर से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए चावल की सुगंध और स्वाद अनूठा है। वहीं महुआ मिलेट लड्डू जो महुआ और मिलेट से बने

जशप्योर ब्रांड को विश्व विख्यात बनाने में डॉ. रवि मित्तल का सराहनीय योगदान

जशप्योर ब्रांड को विश्व विख्यात बनाने में तत्कालीन जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल का योगदान सराहनीय है। डॉ. रवि मित्तल ने यहां के आदिवासी लोगों के हुनर को पहचाना और उनके हुनर के उत्पादों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के भरपूर प्रयास किये। आज विश्व भर में जशप्योर ब्रांड को जो पहचान मिली है वह रवि मित्तल के कारण ही है। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो कदम उठाये थे उससे आज उनकी आजीविका सुगम हो गई है। रोजगार के साथ-साथ उनके जीवन में भी बदलाव आया है। डॉ. रवि मित्तल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रवि मित्तल साफ्ट स्पोकन, बैलेंस और रिजल्ट देने वाले आईएएस माने जाते हैं। उन्हें कांग्रेस शासन काल में जशपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया था। मगर निर्विवाद छवि के होने की वजह से नई सरकार बनने के बाद भी उन्हें वहां कंटीन्यू करना बेहतर समझा गया। चूकि जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है, इसलिए रवि मित्तल की वर्किंग से वे वाकिफ थे। डॉ. मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है। वे 2018 में बगीचा एसडीएम भी रह चुके हैं। जशपुर के जिला कलेक्टर के रूप में मित्तल ने कई उत्पादों के साथ ब्रांड को लॉन्च करने की योजना तैयार की थी। इस ब्रांड में उन उत्पादों को शामिल किया गया है जिनकी आपूर्ति जिले के अलग-अलग स्थानों से की जाती है। रवि मित्तल ने जशप्योर ब्रांड को लेकर कहा, जशप्योर ब्रांड प्रामाणिकता के साथ-साथ प्रकृति की अदम्य सुंदरता का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य, पोषण और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतरीन ब्रांड है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जशपुर जिले के आदिवासियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने में रवि मित्तल के प्रयास सराहनीय हैं। यह पहल न केवल आदिवासी समुदायों को सशक्तबना रही है बल्कि इन अद्वितीय, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि समूहों द्वारा महुआ, कोदो, चावल, हर्रा, टाउ कटहल, इमली चाय, माउथ फ्रेशनर आदि बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं उनके समूह द्वारा महुआ से लड्डू बनाया जा रहा है। साथ ही कई महिलाएं खुद ही ऑनलाइन उन उत्पादों को बेचने का काम करती हैं, जिससे उनकी कमाई होती है। स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की पहल से जशप्योर ब्रांड के नाम से उत्पादों को बेचा जा रहा है। इसके लिए एक अलग से वेबसाइट भी बनाई गई है, ताकि इन उत्पादों की बिक्री के लिए आसानी से मार्केट उपलब्ध हो सके और लोगों तक जल्द से जल्द और आसानी से इन उत्पादों की जानकारी पहुंच सके। यकीनन डॉ. रवि मित्तल ने एक ऐसे जिले को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है जो कि मुख्यधारा से कटा और आदिवासी जनजातियों से छूटा हुआ है। उनकी अभिनव पहल और दूरदर्शी नजर ने इस जिले की असीमित संभावनाओं को पहचान कर उसे एक सशक्त दिशा प्रदान की है। उनकी इस पहल ने ना सिर्फ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि उनके परिवारों को भी मजबूती प्रदान की है।

यह लड्डू पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। यह लड्डू विशेष रूप से बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। ऑनलाइन बिक्री के मामले में भी जशपुर ब्रांड के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का

जशप्योर ब्रांड से हो स्व-सहायता समूह की महिलाओं का उत्थान : मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय

जशपुर से ताल्लुक रखने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार न केवल ब्रांड के माध्यम से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों का उत्थान कर रही है, बल्कि देश के सामने जिले की समृद्ध विरासत को भी प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे इस पहल पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि इसकी सफलता देश भर में इसी तरह के प्रयासों को प्रेरित करेगी, जिससे स्थायी आजीविका और मजबूत समाज का निर्माण होगा। जनजातीय समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित-संवर्धित हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में ही जनजाति समाज का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। साय ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में मैंने प्रदेश के जनजाति समुदाय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के संघर्ष और पीड़ा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की व्यथा को समझा और एक आदिवासी बहुल नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पर्याप्त मात्रा में है। कुल 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विक्रय महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। वनोपजों से जुड़ी प्रोत्साहक नीतियों का लाभ उठाकर स्व सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी कार्यरत है। इस ब्रांड के माध्यम से जशपुर जिले की महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक

छत्तीसगढ़ की माटी, परंपरा और स्वावलंबन का प्रतीकः शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सांस्कृतिक धरोहर, जनजातीय परंपराओं और ग्रामीण आत्मनिर्भरता से प्रेरित जशप्योर ब्रांड की भूरी-भूरी प्रशंसा की। चौहान ने कहा, जशप्योर मात्र एक ब्रांड नहीं, यह छत्तीसगढ़ी माटी की सुगंध, आदिवासी बहनों की तपस्या और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। इनमें केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि जनजातीय समुदाय का श्रम और गौरव समाहित है। यह पहल स्थानीय उत्पादन, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी कौशल को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है।

स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। इसी तरह मिलेट आधारित पास्ता, यह पास्ता पारंपरिक गेहूं के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए एक उत्तम विकल्प है। इनके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाउ और महुआ से बने कई प्रोडक्ट ने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। जशप्योर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक गुण इसका मुख्य कारण है। जशप्योर के तहत जशपुर ब्रांड का हर उत्पाद इन महिलाओं की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। जशपुर ब्रांड के उत्पाद अब ऑनलाईन भी उपलब्ध हैं, जहां से इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता

रवि मित्तल जी के आइडिया ने बदल दी जिंदगी

जशपुर के प्रोडक्ट पर 2500 लोग काम कर रहे हैं। स्व-सहायता समूह के साथ प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन नियमित सेल नहीं कर पा रहे थे। साथ ही सामान की पैकेजिंग सही नही होती थी जिसके कारण सामान की सेल कम हो रही थी। तब तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल जी के आइडिया ने यहां के लोगों की जिंदगी बदल दी। जशप्योर ब्रांड का आइडिया उनका ही था। उनके कारण ही जशपुर में बने सामानों को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। देश के कई शहरों में जशप्योर ब्रांड के स्टोर लगे हुए हैं। साथ ही लोगों को भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। स्व-सहायता समूह को बताने वाले कोई नही थे। इसके अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट लाए। आज जशपुर के अंदर 70 प्रोडक्टस हैं। 25-30 स्व-सहायता समूह हैं जिनमें प्रत्येक स्व-सहायता समूह में 12 महिलाएं हैं। अमेजन प्लेटफार्म पर जशपुर प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पान्स मिल रहा है। अन्य प्लेटफार्म पर लाने की योजना है। भोपाल, रायपुर और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर काउंटर बनाया गया है, जहां पर जशप्योर ब्रांड के सामान रखे गये हैं। हमारी योजना है कि देश के सभी राज्यों के एयरपोर्ट पर स्टाल लगाये जाये। फीडबैक के लिए सारे राज्यों में स्टॉल लगाते हैं। हमारा National Food Technologies of India के साथ एमओयू है। वहां पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भेजा लाता है। कोरोनाकाल में सबसे पहले महिलाओं ने महुआ से सैनिटाईजर बनाया था। जिसे अच्छा रिस्पांस मिला। कोरोना अब खत्म हो गया तो महिलाएं बेरोजगार हो गई। उसके बाद इन्होंने जशप्योर ब्रांड से जुड़कर काम कर रही हैं।

समर्थ जैन, खाद्य प्रसंस्करण सलाहकार, जिला जशपुर

है। इसके साथ ही, देशभर में विभिन्न ऑफलाइन स्टोर्स पर भी ये उत्पाद उपलब्ध हैं, जो इस ब्रांड की व्यापक पहुंच का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने बगिया गांव को दिलाई अलग पहचान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाता जशपुर जिले की बगिया गांव से है। इस गांव की महिलाएं और स्व सहायता

जशप्योर ब्रांड से आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं

जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सफल प्रयास है। इस ब्रांड के माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। जशप्योर द्वारा निर्मित जशप्योर का हर उत्पाद इन महिलाओं की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। जशप्योर का यह जशपुर ब्रांड केवल एक व्यापारिक नाम नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं के परिश्रम, समर्पण और गुणवत्ता की एक कहानी है। जशपुर ब्रांड के माध्यम से अब पूरे भारत में लोग इस स्वाद और गुणवत्ता का आनंद उठा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। यह ब्रांड भविष्य में और अधिक लोकप्रिय हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसका अब सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

समूह के जरिए जिन उत्पादों का निर्माण किया जाता है, उन्हें अब देश में एक अलग पहचान मिल रही है। इन्हीं उत्पादों को जशपुर ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जा रहा है। बगिया वही गांव है, जहां मुख्यमंत्री साय का बचपन बीता और यहीं से सरपंच का चुनाव जीतकर उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरु आत की। वे प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर पहुंच गए हैं और

जशपुर की बेटियां क्रिकेट के पिच पर कर रहीं कमाल

क्रिकेट को भारत में खेल नहीं बल्कि जुनून के रूप में जाना जाता है। इस जुनून का रंग अब जशपुर की बेटियों में भी नजर आ रहा है। जहां जशपुर की बेटियां ना सिर्फ राज्य अपितु राष्ट्रीय स्तर पर जिले का परचम लहराने के लिए तैयारी कर रहीं हैं। इसमें विशेष यह है कि जशपुर जिले में संचालित प्री मेट्रिक बालिका छात्रावास इचकेला की 03 बालिकाओं का चयन अम्बिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 महिला अंडर-17 में अच्छे प्रदर्शन के द्वारा रजत पदक प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के अंडर-17 दल में हो गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने गांव को विश्व में एक अलग पहचान दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में स्व-समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ की थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्व-सहायता समूहों में महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें।

मुख्यमंत्री का कहना है कि स्व-सहायता समूहों में महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें।

हरी सब्जी, फलों की खेती में भी नंबर वन जशपुर

जशपुर में अधिकांश आबादी का मुख्य

जशपुर में कटहल मेला का हुआ आयोजन

प्रदेश में शासन द्वारा फसलों के प्रसंस्करण, नवाचार और उत्पादित फसलों के लिए विपणन के तौर-तरीकों का प्रशिक्षण देकर उनके आय में वृद्धि के साथ ही जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत जिला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में कटहल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कटहल की उपयोगिता, अधिक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग, कटहल से नवाचार एवं इससे बनने वाले अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी गयी। मेले में कटहल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसमें किसानों द्वारा लाए गए सबसे बड़े और सबसे लंबे कटहल को पुरस्कृत किया गया। कटहल जशपुर के मुख्य फल उत्पाद में से एक है। किसानों के लिए यह एक आजीविका का साधन भी है। जिले में बड़े पैमाने पर कटहल का उत्पादन होता है। जिससे देखते हुए किसानों की आय में वृद्धि में कटहल अहम भूमिका निभा सकता है। कटहल के प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं।

आधार कृषि है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वर्षा कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर है। यहां चावल की कई किस्में सुगंधित चावल, दालें, मक्का, रामिल और गेहूं सहित। पिछले दो दशकों में बागवानी ने गति प्राप्त की है और यहां आम, लिची, नाशपाती, काजू और स्ट्रॉबेरी की

विभिन्न उत्पादों के सृजन से आत्मनिर्भर बन रही स्वसहायता समूह की महिलाएं

खेती भी हो रही है। जशपुर जिला तेजी से राज्य का सब्जी केंद्र बन रहा है। यह अन्य हरी सब्जियों के साथ बड़ी मात्रा में टमाटर और मिर्च का उत्पादन करता है। जशपुर के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 42 प्रतिशत वन कवर है। वानिकी गतिविधियों और वन उत्पादन संग्रह इसकी पारंपरिक आर्थिक

मुझे रोजगार भी मिला और आत्म सम्मान भी मिला

मैं भी स्व-सहायता समूह की सदस्य हूं। मैं 2019 में जुडी हूं। जशपुर सेंटर के शुरू होने से बहुत तरक्की मिली है। पहले मैं गृहणी थी लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर बन गई हूं। मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हूँ। जशपुर में सभी महिलाएं आदिवासी हैं। मेरे परिवार में पति, 2 बच्चे, सासू मां हैं। मेरे पति घर में रहते हैं और आजीविका मैं संभालती हूँ। मुझे 10,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है। यह उस समय के कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल जी की सोच है और उनके विजन के हिसाब से ही कार्य किया जा रहा है। मैं कभी चार लोगों के साथ भी खड़ी नही हुई। रवि मित्तल जी ने यह प्रयास किया उन्होंने ने ही मुझे आगे बढ़ाने का संबल दिया। NIFT दिल्ली में जशपुर का स्टॉल लगाया। वहां पर प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। मैं 4-5 महिलाओं को लेकर गई। दिल्ली के भारत मंडपम में भी हमने स्टॉल लगाया है। इसके अलावा सोनीपत हरियाणा में International Confrance of Millet के तहत स्टॉल लगाया था, जहां पर तत्कालीन मंत्री चिराग पासवान आये थे। हमने उन्हें जशपुर की बास्केट दी थी, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया था। और हमारे उत्पादों को सराहा था।

अनेश्वरी भगत

गतिविधि रही हैं। फिर भी, कई वन उत्पादन हैं जो स्थानीय आबादी के लिए अच्छी बाजार क्षमता प्रदान करते हैं। तेंदूपत्ता, चिरौन्जी, शतावार, गम, साल, हारा, लाख आदि यहां के प्रमुख वन उत्पाद हैं। जशप्योर ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले उत्पाद जैसे कैमोमाइल चाय, ढेकी कुटा चावल, देसी गाय का शुद्ध घी और महुआ गोंद के लड्डू इन दिनों लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इन उत्पादों का कच्चा माल मध्य भारत के उपजाऊ क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर वस्तु उच्चतम गुणवत्ता की है।

जशप्योर ब्रांड में शामिल प्रमुख उत्पाद

कैमोमाइल चायः यह चाय पूरी तरह से प्राकृतिक कैमोमाइल फूलों से बनाई जाती है, जिसमें कोई कृत्रिम रंग या स्वाद नहीं

अपने पैरों पर खड़ी हो रही महिलाएं

हमारे स्व-सहायता समूह में सभी आदिवासी महिलाएं हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति की भी महिलाएं हैं। मशीनों में धान कुटाई करती हैं। आटा चक्की चलाती हैं। पंचायत की तरफसे स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कचरा वाहन के लिए Tricycle दी गई है। और इस कार्य के लिए उन्हें 10 हजार रूपये मानदेय भी दिया जा रहा है। ये महिलाएं दोना पत्तल भी बना रही हैं। इससे हमारी आमदनी होती है, महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। हमारे परिवार के भी हालात सुधर गये हैं। हम अब आत्मनिर्भर हो गये हैं।

फूलमति राजवाड़े, सदस्य, मां शारदा स्व-सहायता समूह

होते।

कोल्ड प्रोसेस्ड राइस जवाफूल (ढेकी कुटा चावल): यह चावल पारंपरिक तरीके से ढेकी से कूटा जाता है, जो सामान्य चावल के मुकाबले अधिक पोषण प्रदान करता है।

महुआ गोंद के लड्डू: हाथ से तैयार किए गए महुआ गोंद के लड्डू, जो स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से बेहद खास होते हैं। महुआ का गोंद पारंपरिक आदिवासी खाद्य संस्कृति का हिस्सा है।

शुद्ध देसी गाय का घी: यह घी पूरी तरह से देसी गाय के दूध से बनता है, जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है।

ब्लू पी और लैवेंडर टीबैग: यह चाय ब्लू पी और लैवेंडर के फूलों से बनाई जाती है, जो छाया में सुखाए गए होते हैं।

टोकरी बनाकर बन रही है लखपति दीदियाँ

जशप्योर ब्रांड से नई पहचान मिली

मैं कभी ट्रेन में भी नही बैठी थी। मैं दो बार दिल्ली गई। मैंने दिल्ली में अपनी कमाई से 4000 रूपये की घड़ी खरीदी। जशपुर से बाहर भी नही निकली थी। लेकिन जशपुर के उत्पादों के कारण बाहर घूमने को अवसर मिलता है। साथ ही रोजगार पाकर आत्मनिर्भर हो गई हूं। जशप्योर ब्रांड के कारण हमें नई पहचान मिली है। मेरे साथ मेरे घरवालों की जिंदगी भी बेहतर हो गई है। जब से जशपुर में जशप्योर ब्रांड आया है तब से सभी लोगों की जिंदगी आसान हो गई है।

फूलमनी प्रभा साय

स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित टोकरियां

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है और उनको विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। जशपुर जिले के दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के द्वारा छिंद कांसा से बनाई हुई टोकरी एवं अन्य उत्पाद काफी टिकाऊ एवं मनमोहक हैं। यह मूलतः जशपुर जिले के काँसाबेल विकासखण्ड की स्व सहायता समूह की दीदिओं द्वारा बनाया जा रहा है और अच्छी आमदनी प्राप्त की जा रही है। चूंकि यह अभ्यास लगभग 30 साल पुराना है परंतु इसमे उद्यमिता की छाप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तत्पश्चात छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के प्रयास से संभव हो सका है। वर्तमान में लगभग 100 महिलाएं इस उद्योग में जुड़ी हैं और सतत् रूप से उत्पादन एवं विक्रय कार्य में लगी हुई है। आकर्षक एवं सुन्दर छिंद कांसा की टोकरी होने की वजह से जिले में और राज्य के कोने-कोने से इसकी सतत मांग बनी रहती है। जशपुर जिला उत्पादों की विशेष ब्रांड जशप्योर के बनने के पश्चात भारत के अन्य राज्यों से भी लगातार मांग बढ़ रही है, जिससे इस उद्योग में जुड़ी महिलओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। यह कार्य काँसाबेल विकासखण्ड के कोटानपानी ग्राम पंचायत के अधिकतर घरों की महिलायें द्वारा किया जा रहा है कोटानपानी ग्राम पंचायत मूलतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है।

417 ग्राम पंचायतों में योजना का किया जा रहा बेहतर क्रियान्वयन

भारत सरकार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले के आठों विकासखंडों के चिन्हांकित 417 ग्राम पंचायतों में महत्वाकांक्षी योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 25 प्रकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है और योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जशपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहां विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को केन्द्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान के तहत आधार कार्ड, सभी का आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, सिकल सेल जांच, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण और छात्रावास-आश्रम का निर्माण किया जा रहा है।

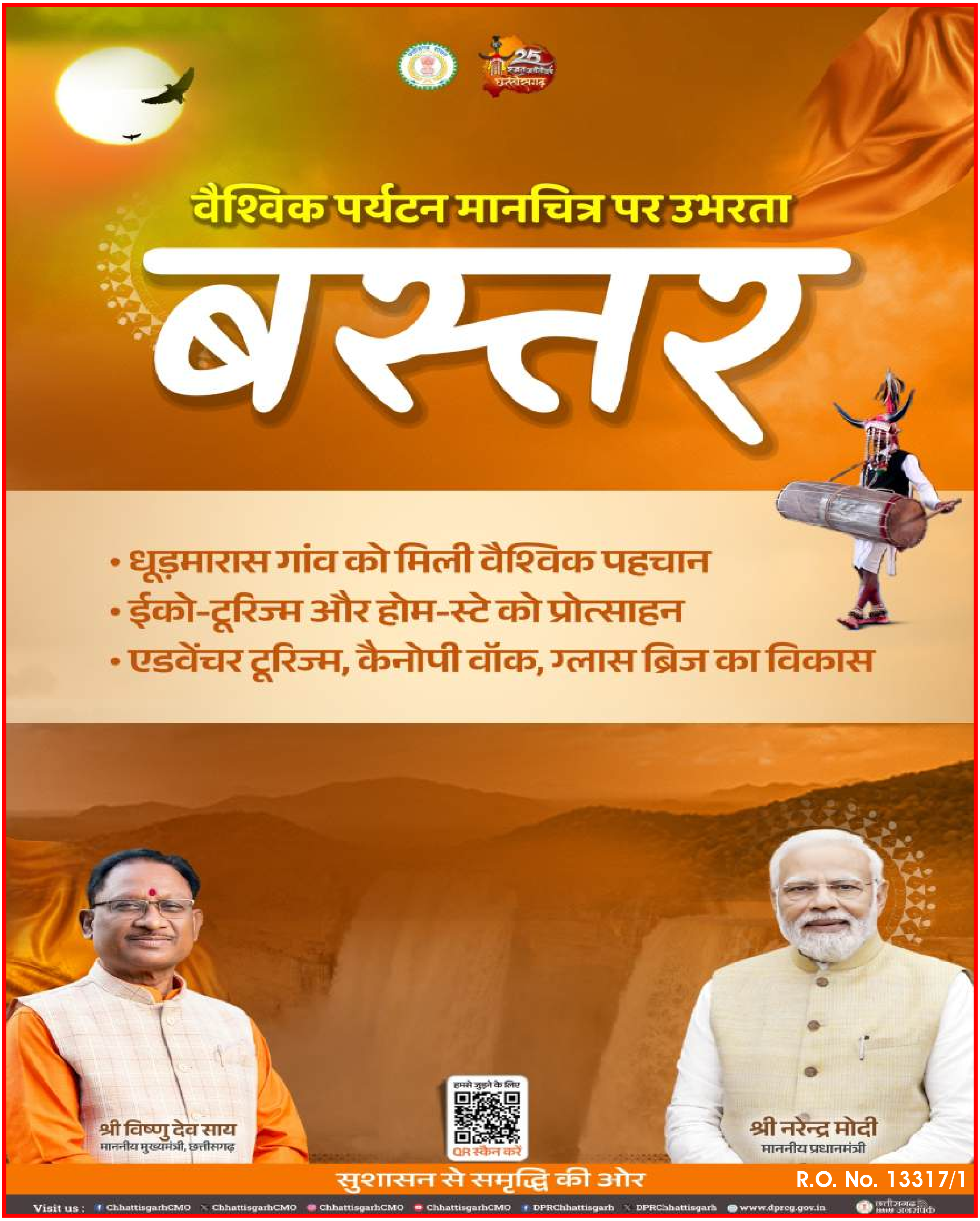
वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर उभरता
बस्तर
• धूड़मारास गांव को मिली वैश्विक पहचान
• ईको-टूरिज्म और होम-स्टे को प्रोत्साहन
• एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक, ग्लास ब्रिज का विकास
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
सुशासन से समृद्धि की ओर
R.O. No. 13317/1
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
ई- पंजीयन
से अब बेहद आसान है
भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया
सुगम मोबाईल एप
PAN व आधार इंटीग्रेशन
स्टांप वेंडर तक पहुंच आसान
जिओ रेफरेंसिंग प्रणाली
My Deed माड्यूल
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
R.O. No. 13282/2
(अधिक जानकारी के लिए
https://industries.cg.gov.in पर विजिट करें)
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

संगठन में सामंजस्य और गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती

विजया पाठक

मध्यप्रदेश भाजपा को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वे वीडी शर्मा का स्थान लेंगे, जो लंबे समय से अतिरिक्त कार्यकाल पर चल रहे थे। पार्टी के अंदर यह बदलाव कई दिनों से चर्चा में था, लेकिन अंतिम निर्णय को लेकर असमंजस बना हुआ था। खंडेलवाल के नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पसंद हेमंत खंडेलवाल ही थे। खंडेलवाल के संगठनात्मक अनुभव, संतुलित छवि और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे रिश्ते को देखते हुए हाईकमान ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।

सकारात्मक दिशा मिलेगी

भाजपा के लिए हेमंत खंडेलवाल का अध्यक्ष बनना एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। उनकी स्वच्छ छवि, सांगठनिक पकड़ और मुख्यमंत्री का भरोसा- ये सभी उनकी ताकत हैं। लेकिन साथ ही, गुटबाजी, नाराज नेताओं को साधना और सत्ता-संगठन का संतुलन बनाना उनकी परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा में और कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और उर्जा मिलेगी।

संगठन और सत्ता का सामंजस्य होगी सबसे बड़ी चुनौती

खंडेलवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता और संगठन के बीच सामांजस्य बनाए रखना होगी। मोहन सरकार के कार्यकाल में संगठन की भूमिका को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, तथा सत्ता के फैसलों से संगठन को जोड़ने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद संगठन की भूमिका और भी अहम हो गई है। 2029 की तैयारी और 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल उंचा रखना और गुटबाजी को समाप्त करना अनिवार्य होगा।

नाराज नेताओं को मनाना भी चुनौतीपूर्ण

भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लंबे समय से अलग-अलग गुट सक्रिय थे। कई दिग्गज नेता अपने समर्थकों को इस पद पर देखना चाहते थे। लेकिन अंततः खंडेलवाल के नाम पर सहमति बनी। अब नाराज नेताओं को मनाना, उन्हें साथ लेकर चलना और संगठन में सामूहिक नेतृत्व की भावना स्थापित करना खंडेलवाल के लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी।

गुटबाजी से निपटना प्राथमिकता

प्रदेश भाजपा में लंबे समय से क्षेत्रीय गुटबाजी हावी रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का गुट, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव, संगठन के पुराने नेताओं का दबदबा और संघ से जुड़े नेताओं की अलग लॉबी- इन सभी के बीच संतुलन बनाना खंडेलवाल के कौशल की परीक्षा लेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे इस चुनौती को पार कर लेते हैं तो आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को सीधा लाभ मिलेगा।

मोहन यादव का भरोसा, संकेत बड़े बदलाव के

मुख्यमंत्री मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के बीच पुराने समय से ही अच्छे संबंध रहे हैं। सूत्रों की मानें तो खंडेलवाल की ताजपोशी के साथ ही प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संगठनात्मक पदों पर नए चेहरों को मौका देना, कार्यकर्ता संवाद बढ़ाना और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क खड़ा करना उनकी प्राथमिकता होगी।

भविष्य की रणनीति तय करेगी सफलता

प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष पद केवल संगठन का नेतृत्व नहीं बल्कि सरकार और केंद्र के बीच सेतु की भूमिका भी निभाता है। हेमंत खंडेलवाल को अपनी टीम के चयन, कार्यकर्ताओं के सम्मान और विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार की रणनीति पर तुरंत काम शुरूकरना होगा। आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव उनके नेतृत्व की पहली परीक्षा होंगे।

कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी?

कवायद तेज, कशमकश में साय सरकार

हिमांशु गुप्ता का डीजी पदोन्नति पर उठ रहे सवाल

विजया पाठक

1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता के डीजी पदोन्नति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीपीसी के लिए हिमांशु गुप्ता समेत कई अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक यूपीएससी को भ्रामक एवं गलत जानकारी भेजी है। उक्त नियम विरूद्ध पदोन्नति के लेकर अब कार्रवाही की मांग की जा रही है। जबकि नियमानुसार डीजी के पद पर पदोन्नति 1994 बैच के आईपीएस एसआरपी कल्लूरी की होनी थी जिन्होंने अपने सर्विस काल की 30 सालों की मियाद पूरी कर ली है।

एस.आर.पी. कल्लूरी

1995 की वरिष्ठता सूची में हिमांशु नही

हिमांशु गुप्ता 1994 बेच के आईपीएस है लेकिन जब मध्यप्रदेश में 1995 में वरिष्ठता सूची जारी की गई उसमें हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल नही है। जबकि 1995 की वरिष्ठता सूची में गुरजिंदर पाल सिंह और शिवराम प्रसाद कल्लूरी का नाम शामिल हैं। इस प्रकार हिमांशु जब भी वरिष्ठता सूची में आएंगे तो शिवराम प्रसाद के नीचे ही आएंगे। इनकी पहुंच और जुगाड़ का यह आलम है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को भी इन्होंने ठेंगा दिखाया और अपनी वरिष्ठ को गलत तरीके से कायम

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने डीजी हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति पर उठाए सवाल

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने डीजी पद पर आईपीएस हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति को गलत ठहराया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव को शिकायती पत्र लिखकर बताया है कि डीपीसी में राज्य शासन की तरफ से गलत जानकारी दी गई। हिमांशु गुप्ता से पदक्रम सूची में आगे एसआरपी कल्लूरी पदोन्नति से वंचित रह गए। पूर्व गृहमंत्री ने केन्द्रीय गृह सचिव को दस्तावेजी साक्ष्य सहित शिकायत करते हुए इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताया है कि हिमांशु गुप्ता को त्रिपुरा केडर आवंटित किया गया था। इसके बाद केडर ट्रांसफर योजना के तहत आवेदन करने पर मध्यप्रदेश केडर आवंटित किया गया। इसके बाद राज्य विभाजन पर 2000 में छत्तीसगढ़ केडर आवंटित किया गया। डीओपीटी नियम के अनुसार वरिष्ठता क्रम में उनका नाम एसआरपी कल्लूरी के बाद दर्ज होना था। पूर्व गृहमंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ गृह विभाग के कुछ अफसरों से मिलीभगत कर हिमांशु गुप्ता ने अनियमित पदोन्नति प्राप्त की है। इसके लिए यूपीएससी को भ्रामक जानकारी भेजी गई है। पूर्व गृहमंत्री ने पत्र में यह भी बताया है कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह वरिष्ठता क्रम में हिमांशु गुप्ता से उपर है। न्यायालय के आदेश के परिपालन में नियमानुसार उनकी डीजी पद पर पदोन्नति का लिफाफा सील कर डीजी का एक पद आरक्षित रखना चाहिए था। लेकिन, इसे भी दरकिनार कर दिया गया।

रखवाने में सफल रहे। मसला दरअसल यह है कि हिमांशु गुप्ता त्रिपुरा केडर के आईपीएस हैं। इसके बाद केडर ट्रांसफर योजनांतर्गत हिमांशु गुप्ता की स्वयं की मांग पर उन्हें मध्यप्रदेश केडर आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तब इन्हें छत्तीसगढ़ केडर आवंटित किया गया। हिमांशु गुप्ता केडर ट्रांसफर अंतर्गत मध्यप्रदेश भारतीय पुलिस सेवा की सूची में सम्मलित हैं। नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा का जो अफसर केडर ट्रांसफर के अंतर्गत किसी राज्य में स्थानांतरित होता है तो उसका नाम उस राज्य के पदक्रम सूची में वरिष्ठता कम में अपने बैच में अंतिम

क्या छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की पसंद का बनेगा डीजीपी?

भूपेश बघेल

हिमांशु गुप्ता

छत्तीसगढ़ में डीजीपी पद के लिए रस्साकशी चल रही है। आश्चर्य की बात है कि पद के लिए जिसका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। वह न तो सबसे वरिष्ठ है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस हिमांशु गुप्ता की। गुप्ता सबसे ज्यादा दागदार हैं। सूत्रों के मुताबिक इस अधिकारी को डीजीपी पद पर आसीन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और उनके दो खासमखास पूर्व आईपीएस, वर्तमान गृहमंत्री शामिल हैं। प्रदेश सरकार जहाँ संवैधानिक रूप से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए विकास की नई राह तय कर रही है, वहीं टॉप क्लास नौकरशाही के असंवैधानिक फैसलों से पीड़ित अधिकारी-कर्मचारी भी अदालतों का रूख कर रहे हैं। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन वरिष्ठ अधिकारियों का दुख-दर्द है, जो कई सालों से राज्य सरकार की सेवा में जुटे हैं। प्रभावशील अधिकारी मनमानी में उतारूहैं। मुख्य सचिव भी क़ानूनी नहीं बल्कि राजनैतिक फैसलों पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को पांच साल देखा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में घोटाले के जो प्रतिमान स्थापित हुए वे आठवें आश्चर्य के रूप देखे जाने चाहिए। भूपेश

स्थान पर प्रविष्ट किया जाता है। इसलिए कहना गलत नही है कि वरिष्ठता क्रम और डीओपीटी के नियम अनुसार एसआरपी कल्लूरी का नाम डीजी पद के लिए दर्ज किया जाना था।

पदोन्नति समिति को किया गुमराह

हिमांशु गुप्ता द्वारा गृह विभाग के चंद अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अनियमित पदोन्नति प्राप्त की है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली को अपनी पदोन्नति के सम्बंध में गलत एवं भ्रामक जानकारी भेजी गई। उक्त मामले में तथ्य यह है कि केंद्रीय न्यायिक अभिकरण द्वारा दिनांक 30.04.2024 को 1994 बैच के

बड़ा सवाल : वरिष्ठता क्रम और डीओपीटी के नियम अनुसार एसआरपी कल्लूरी का नाम डीजी के लिए क्यों नहीं किया दर्ज?

आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) के अनिवार्य सेवा निर्वित आदेश को अपास्त करते हुए समस्त परिणामी लाभ सहित सेवा में वापस लेने के आदेश दिया गया था। जिसे राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इसके बाद जून 2024 के अंतिम सप्ताह में जब डीजी के रिक्तपदों पर पदोन्नति की कार्रवाही की गई। तब माननीय न्यायालय के आदेश परिपालन में नियमानुसार जीपी सिंह के पदोन्नति हेतु लिफाफा सील कर डीजी का एक पद

बघेल के कुशासन में आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा की एक महिला अधिकारी के रंगदारी के किस्से खूब हुए थे। समीर विश्नोई, रानू साहू, अनिल टुटेजा, टामन सिंह सोनवानी, निरंजन दास जैसे आईएएस अधिकारियों का जमीन में बिछ जाना समझ में आता है। आईपीएस अधिकारी भी दलाली में जुट गए। प्रदेश के आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी केंद्रीय जांच एजेंसी के घेरे में हैं। एक राज्य स्तरीय दलाल पुलिस अधिकारी जो सौम्या चौरसिया का अधिकृत सलाहकार रहे। कबाड़ियों को संरक्षण देकर अवैध कारोबार का

जीपी सिंह

पवन देव

वसूलीकर्ता रहा। सिविल लाइन थाने में बैठकर पत्रकारों के खिलाफ फर्जी प्रकरण बनवाकर पीठ थपथपाने की आदत पाले वाला ये अधिकारी कांग्रेस शासनकाल में पुलिसिया भ्रष्टाचार का चलता फिरता प्रतीक था। भाजपा के अनेक व्यापारी, प्रतिनिधि इस अधिकारी के चलते शरणागत होने की स्थिति में आ गए थे। भाजपा शासन में वापस आई तो सबसे पहले इसी अधिकारी को वनवास में बस्तर भेजा गया था। नक्सली समस्या का हल करने के लिए इसे जिम्मेदारी दी गई थी। इससे परे ये अधिकारी अपने अभिषेक के लिए जी जान लगा दिया है। भ्रष्टाचार से आए पैसे के सदुपयोग का सही समय आने में केवल डेढ़ साल लगे हैं। एकात्मक परिसर में पिछले साल भी इसी महा भ्रष्ट अधिकारी के अभिषेक की चर्चा हुई थी। संगठन के अलावा सरकार के निर्वाचित जन प्रतिनिधि आगे आए तो मामला टल गया। सरकार ने ट्रांसफर से बेन हटा लिया है यानि मंत्री चाहे तो किसी को इधर उधर कर सकते हैं। पुलिस विभाग गृहमंत्री के अधीन है।

आरक्षित रखना चाहिए था। चूंकि जीपी सिंह वरिष्ठता क्रम में हिमांशु से उपर हैं। हिमांशु गुप्ता द्वारा गृह विभाग के अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव से मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक विभागीय पदोन्नति समिति को गुमराह किया गया।

अधिकारी राज में कुछ भी संभव

माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश के परिपालन में जीपी सिंह द्वारा 20.12.2024 को समस्त परिणामी लाभ सहित अपनी सेवा में उपस्थित हुए। छत्तीसगढ में

निरंकुश रहा अरूणदेव का कार्यकाल

छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरूण देव गौतम की अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि प्रदेश में नये डीजीपी का नाम फाईनल होने वाला है। वे अपने नरम प्रशासन कार्यवाही और अपराध नियंत्रण न करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। डीजीपी बनाने के बाद उनकी प्राथमिकता राज्य में क्राइम को कम करना, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और पुलिसिंग सुधार जैसी उम्मीदें लगाई गई थी लेकिन वह इसमें खरे नहीं उतरे।

पवन देव, जीपी सिंह डीजीपी के लिए सबसे उपयुक्त

पवन देव

राज्य के प्रशासनिक मुखिया और जूनियर अधिकारियों की पसंद-नापसंद के चलते डीजीपी का पद विवादों से घिरा बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली के चलते पुलिस मुख्यालय में पुनः गतिरोध कायम हो गया है। दरअसल, आईपीएस पवन देव और जीपी सिंह का नाम प्रस्तावित डीजीपी के चयन हेतु केंद्र को भेजी गई पैनल लिस्ट से हटाये जाने के मामले ने गंभीर रुख ले लिया है। सूत्र तस्दीक करते हैं कि मामले की शिकायत पीएमओ और सीबीआई से किये जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इस याचिका के तथ्यों से सत्ता के गलियारों में हड़कंप है। प्रशासनिक और पुलिस गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के इशारों पर लिए जा रहे फैसलों से छत्तीसगढ़ का राजनैतिक गलियारा सरगर्म है। पवन देव ने याचिका दायर कर अदालत से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। यह भी बताया जाता है कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने को लेकर मुख्य सचिव का कार्यालय ने आपराधिक कार्यशैली का परिचय देते हुए बड़ी धांधली की है, पहली डीपीसी में जीपी सिंह की पदोन्नति से जुड़ा बंद लिफाफा प्रस्तुत करने में कोताही बरती गई। इसके बाद यूपीएससी की अंतिम पैन-लिस्ट से उनका नाम अचानक बाहर कर दिया गया। जीपी सिंह के अलावा पवन देव का नाम भी डीजीपी पद की पैनल लिस्ट से आखिरी समय हटाए जाने का मामला विवादों से घिर गया है। डीजीपी के लिए नियुक्ति ने इस बात पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या योग्यता की बलि नौकरशाही की जड़ में समा गई है। प्रशासनिक और पुलिस हलकों के जानकार सूत्रों के अनुसार, यूपीएससी की विभागीय पदोन्नति समिति ने डीजीपी पैनल को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह आदेश के तहत 13 मई को बैठक की गई थी। इस सूची में विचार के लिए 04 नाम- अरुण देव गौतम, पवन देव, हिमांशु गुप्ता और जीपी सिंह शामिल किये गए थे। मुख्य सचिव कार्यालय ने रहस्यमय तरीके से कैंची चलाते हुए केंद्र सरकार को भेजी गई पैनल में सिर्फ दो अधिकारियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई, जबकि शेष दो अधिकारियों का पत्ता बगैर किसी ठोस कारणों के साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक मौजूदा प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम और डीजी हिमांशु गुप्ता का ही नाम अंतिम सूची में जगह बना पाया। जबकि प्रक्रियागत पात्रता के बावजूद जीपी सिंह और पवन देव का नाम पैनल से हटा दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनकी लॉबी जीपी सिंह की डीजीपी पद पर नियुक्तिको रोकने के लिए जोर-शोर से जुटी हुई है। राजनैतिक गलियारों में चर्चा है कि डीजीपी की कुर्सी पर जीपी सिंह के बैठते ही बघेल समेत उसके गिरोह के कई आपराधिक तत्व हवालात में नजर आ सकते हैं। फिलहाल बीजेपी शासनकाल में भी उनका फीलगुड यथावत जारी है।

तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के सेवानिवृत्ति के बाद 5.2.2025 को डीजी का एक पद रिक्तहुआ। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन हेतु फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में रिव्यू डीपीसी की मीटिंग आयोजित की गई। उक्त बैठक में नियमानुसार जीपी सिंह की पदोन्नति 2.7.2024 से जिस पद को आरक्षित रखा जाना था, उसमें 5.2.2025 को हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति की अनुशंसा की गई। वही जब लोक सेवा आयोग पुनः प्रस्ताव भेजा गया तब षड्यंत्रपूर्वक पदोन्नति 2.7.2024 दिखाई गई। अब इसमें गृह विभाग से चंद अधिकारियों की मिलीभगत से 2.7.2024 डीजी पद निर्माण की जुगत केबिनेट में लगाई गई थी, जो नियमतः तो संभव नही हो सकती थी। लेकिन जंगल राज के अधिकारी शासन में कुछ भी असंभव नही है। उपरोक्त सारे तथ्यों को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिमांशु गुप्ता की पदोन्नति नियम विरूद्ध ही नही षड्यंत्रपूर्वक अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। हिमांशु गुप्ता द्वारा डीजी के पैनल हेतु प्रस्ताव में पदोन्नति दिनांक रिव्यू

जीपी सिंह के मामले में कांग्रेस लगा रही अड़ंगा

जीपी सिंह

जीपी सिंह का ट्रेक रिकॉर्ड बेहतर आँका जाता है। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त तत्वों को उनके असल ठिकाने भेजे जाने के मामले में जीपी सिंह की गिनती कारगर और योग्य आईपीएस अधिकारियों के रूप में होती है। जीपी सिंह के शासन-प्रशासन की मुख्यधारा शामिल होने के अंदेशे मात्र से भूपेश गिरोह की नींद हराम बताई जाती है। सूत्र तस्दीक करते हैं कि भूपेश गिरोह के बचाव के मद्देनजर केंद्र सरकार को गलत जानकारी देकर दोनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पैनल लिस्ट से दरकिनार किया गया है। यही नहीं प्रदेश के मुखिया की पसंद-नापसंद का हवाला देते हुए अनधिकृत कदम उठाये गए हैं। अब राज्य सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दिए जाने का मामला सुर्ख़ियों में बताया जा रहा है। जीपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कांग्रेस राज से ही तलवारें खींची बताई जाती हैं। भूपेश राज में जीपी सिंह के कई क़ानूनी फैसलों से तत्कालीन मुख्यमंत्री के अरमानों पर पानी फिर गया था। बताया जाता है कि नान घोटाले में निर्दोषों को फंसाने और उनके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने को लेकर जीपी सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्पष्ट ना कर दी थी। जबकि तत्कालीन सुपर सीएम अनिल टुटेजा को जमकर फटकार लगाई थी। इस मामले में टुटेजा का माफीनामा सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था।

डीपीसी के अनुशंसा के विपरीत दर्ज कराई गई। जबकि वास्तव में दिनांक 5.2.2025 को डीजी के रिक्त पद पर शिवराम प्रसाद कल्लूरी को पदोन्नत किया जाना चाहिए था न कि हिमांशु गुप्ता को।

25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर कांग्रेस नेताओं की जान ले ली थी। उस समय बस्तर आईजी हिमांशु गुप्ता थे। तब हिमांशु गुप्ता को पुलिस मुख्यालय रायपुर बुला लिया गया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था। जबकि उस दिन मयंक श्रीवास्तव छुट्टी पर थे और उनकी कोई गलती नही थी। यहां सवाल उठता है कि जब एसपी को निलंबित किया गया लेकिन हिमांशु गुप्ता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस समय हिमांशु गुप्ता की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। कहा गया था कि हमले से समय करीब 300 नक्सली थे और इनका क्षेत्र में कई दिनों से मूवमेंट था। फिर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी। और दर्जनों लोग घायल हो गये थे।

हिमांशु गुप्ता के कारण बर्बाद हो गया मेरा घरः अखिलेश खंडेलवाल

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताई थी व्यथा

मैं अखिलेश खंडेलवाल गोकुलपुर धमतरी का निवासी हूं। हमारा एक सुखी परिवार था। अब हमारा परिवार पुरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता हैं। हमारा हिमांशु गुप्ता से संबंध तब से है जब वे 2004 में पुलिस अधीक्षक जगदलपुर थे। मेरी पत्नी का बुटांक हैं और हम एग्जिबीशन के लिए उनकी मदद लेने के लिए गए थे। फिर वह धमतरी एसपी बने। 13/02/2005 से 31/01/2006 तक वे बी 4 अमलतासपुरम् जो कि मेरे बाजू में रहते थे। मेरी पत्नी हिमांशु गुप्ता को राखी बांधती थी। उनका हिमांशु गुप्ता से भाई-बहन का संबंध था। धमतरी में उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गयी। चूंकि उनका भाई-बहन का संबंध था। मैंने ज्यादा ध्यान नही दिया। तब मेरी पत्नी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। बात-बात में वह गुस्सा एवं गलत बात करने लगी। जब इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि यह सब यह हिमांशु गुप्ता के कहने पर कर रही है। मेरी पत्नी सविता रानीगंज अपने मायके चली गयी। वहां थोड़े दिनों रहने के बाद मुझे ससुराल वालों में मेरे बड़े बेटे रजत खंडेलवाल के माध्यम से बताया कि सविता फेसबुक में मुन गुप्ता नाम के व्यक्ति से चेटिंग करती है। मेरे ससुराल वालों मेरा पूरा सहयोग दिया। मुझे यह पता हैं कि सविता को कम्प्यूटर का ज्ञान बहुत कम है। उसका आईडी हिमांशु गुप्ता ने बनाया तथा अपना फेक आईडी मुन गुप्ता के नाम से बनाई, जिसमें उसने मेरी पत्नी की फोटो लगायी पर अपनी जगह एक लड़की की कार्टून फोटो लगायी। जब वह रानीगंज से धमतरी आयी तब उसके कम्प्यूटर में खराबी आ गयी। जिसको सुधरवाने के लिए मेरे स्टाफ के दिनेश जगताप को दिया। दिनेश जगताप ने यह बात रजत को बताई। मेरा बेटा जो कम्प्यूटर साइंस में बैंगलूरूमें पढाई कर रहा था तथा उसको इस बात का एहसास था कि मां फेसबुक में चेंटिंग कर रही है तो उसने फेसबुक में पासवर्ड बदलने के लिए एसएमएस किया। चूंकि वह आईडी सविता की थी। इसलिए वह कोड सविता के मोबाइल नम्बर में आया। तब मेरे बेटे रजत ने वह नम्बर अपनी मां से पूछा। चूंकि सविता को कम्प्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नही होने की वजह से कोड रजत

हिमांशु गुप्ता

सविता खंडेलवाल

को दे दिया। इस चेटिंग को अवलोकन करने के पेज नंबर 25, 26, 30 से पता चलता है कि मुन गुप्ता और कोई नही हिमांशु गुप्ता हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तब मैंने साइबर क्राइम रायपुर को जांच के लिए आवेदन दिया जिसकी जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त नही हुई हैं। मैंने इस केस की चेटिंग का प्राइवेट एजेन्सी से कराया जिसमें मुन गुप्ता स्पष्ट रूप से हिमांशु गुप्ता का नाम आया है। आईपी कोड जगदलपुर आईजी आफिस का हैं जिसकी जांच की जा सकती है। मैंने हिमांशु गुप्ता

को रायपुर में फ्लैट दिलाया था। हिमांशु गुप्ता ने बाद में किराया देने भी बहुत परेशान किया। वह मेरी पत्नी को उक्सा रहा था। बहुत जल्दी मेरी पत्नी हिमांशु गुप्ता के इशारे पर नाचने लगी और पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करती। मेरी पत्नी न्यायालय में महिला उत्पीड़न का केस हार चुकी है। अब वह मेरे बेटे को भी प्रताडित कर रही है। अब इन सब प्रताड़ना की वजह से वह बैंगलूरू से पढ़ाई छोड़कर वापस धमतरी आ गया। हिमांशु गुप्ता की मेरी पत्नी के जरिये मेरी प्रॉपर्टी पर नजर है। वर्तमान में सविता दिल्ली के सेक्टर 06 द्वारका में रहती है। जबकी सविता धमतरी में सबको बोलकर गयी थी कि मैं अपनी बहन जो कि गाजियाबाद में रहती है उनके पास जा रही हूँ। हिमांशु गुप्ता का दिल्ली आना जाना बहुत होता है। मेरा परिवार बर्बाद हो गया तथा मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे डर है कि इन विवाद के चलते मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे।

सविता की मौत के दाग हिमांशु गुप्ता पर लगे हैं...

22 जून 2018 को समाज, परिवार और खुद से जूझती सविता खंडेलवाल ने इसी दिन आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का यह मामला कोई सामान्य घटना इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके तार एक आईपीएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता से जुड़े हुए हैं। बार-बार यह सवाल सामने आता है कि सविता मरी या उसे मरने मजबूर किया गया। सविता खंडेलवाल की आत्महत्या के बाद मृतिका के पति अखिलेश ने अपने बयान में पारिवारिक विवाद का जिक्र किया था। कुछ ऐसा ही बयान उनके सुपुत्र रजत ने भी दिया है। सविता के भाई रानीगंज निवासी सुनील खंडेलवाल ने अपने बयान में जिक्र किया है कि उनकी बहिन मानसिक रूप से परेशान थी। वहीं से धमतरी में पदस्थ रहे आईपीएस अधिकारी की भूमिका शुरु होती है। दरअसल, यह पूरा बखेड़ा शुरू ही इस आईपीएस अधिकारी के चलते हुआ और आखिर में सविता अपना सबकुछ हार गई। सविता खंडेलवाल प्रकरण में बहुत सारे तथ्य अनसुलझे रह गए हैं। मामले में दस्तावेजों का अध्ययन करने पर बार-बार एक नाम सामने आता है है जो कि मून गुप्ता का बताया जाता है। ये मून गुप्ता है कौन इसका अध्ययन करने पर सविता खंडेलवाल द्वारा पूर्व में नेशन अलर्ट को की गई अपनी हस्त लिखित शिकायत में तबके आईजी (वर्तमान में एडीजी) हिमांशु गुप्ता का नाम सामने आता है। प्रकरण में जब जांच पड़ताल की थी तो तब के आईजी हिमांशु गुप्ता का नाम सामने आया था। सविता खंडेलवाल ने दिनांक 24 मई 2018 को एक शिकायत लिखी थी। इसी शिकायत में उन्होंने यह लिखा था कि उनके पति अखिलेश खंडेलवाल ने मौखिक तौर पर बोल-बोल कर यह साबित कर दिया था कि सविता और आईजी (वर्तमान एडीजी) हिमांशु गुप्ता के गलत संबंध हैं। शासन-प्रशासन से सविता खंडेलवाल ने इसी मसले पर जांच की मांग की थी जो कि पूरी होने के पहले ही सविता को अपनी मौत को गले लगाना पड़ा। तब उन्होंने लिखा था कि मामले में हिमांशु गुप्ता का मौन रहना भी उनके पति की बातों को समर्थन दे रहा है।

प्रभावशाली हैं हिमांशु गुप्ता

सविता खंडेलवाल ने तब लिखा था कि दरअसल मामले में आईजी हिमांशु गुप्ता बेहद प्रभावशाली है। संभवतः इसी के चलते आज तक हिमांशु गुप्ता किसी बड़ी मुश्किल में नहीं आए और न ही उनसे पूछताछ हुई। तबके एक अन्य आईपीएस जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अनौपचारिक चर्चा में बताते हैं कि सविता खंडेलवाल बार-बार आईजी हिमांशु गुप्ता का नाम लेती थी। यह अपनी पारिवारिक परेशानी के लिए हिमांशु गुप्ता को ही जिम्मेदार ठहराती थीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जिस एलन मस्क ने ट्रंप की मदद की उसके ही खिलाफ खड़े हो गये ट्रंप

विजया पाठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही दोस्त और उद्योगपति एलन मस्क से विवाद आरंभ कर दिया। अपने विवादित बयानों के लिये विशिष्ट पहचान रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर बैठते ही सबसे पहले भारत, फिर चीन और अन्य देशों को टारगेट किया और सभी पर जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाने का फैसला किया। खास बात यह रही कि भारत ने अपने कूटनीतिक रवैये से तो ट्रंप को टैरिफ लगाने के निर्णय से पीछे हटने को मना कर दिया, लेकिन चीन के साथ ट्रंप किसी भी तरह से टैरिफ हटाने को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं। बढ़ते दबाव और राजनीतिक खींचतान के कारण ट्रंप ने फिलहाल चीन पर लगाने वाले 154 प्रतिशत टैरिफ को तीन माह के लिये रोक दिया है। इस बीच ट्रंप के दोस्त और चुनाव में उनकी आर्थिक मदद करने वाले उद्योगपति एलन मस्क से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपने जिगरी दोस्त मस्क से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और ट्रंप के बीच तनाव खुलकर सामने आ चुका है। हालात ये हैं कि दोनों ही दिग्गज सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ धमकियों में भी उलझ गए हैं।

इसलिये हुआ दोनों के बीच झगड़ा

ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप का ऐसा रवैया सामने आया है। इससे पहले भारत के साथ भी यूएस राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ही किया। राष्ट्रपति के तौर पर पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आई। हालांकि, इस बार ट्रेड डील हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मामला, यूएस राष्ट्रपति अलग राह पकड़े ही नजर आए। भले ही उन्होंने भारत के साथ 'दुश्मनी' वाला दांव चला हो लेकिन 'दोस्त' मस्क के साथ हुआ खेल, उनके लिए उल्टा जरूर पड़ गया है।

विवाद के बाद उठने लगे सवाल

डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोस्ती तो जल्दी करते हैं, लेकिन निभाते उसी से हैं जो उनकी शर्तों पर चले। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपने फैसलों से कई साथियों को चौंकाया। उन्होंने उन देशों से हाथ मिलाया जिनसे अमेरिका पहले दूरी रखता था। ट्रंप के बदले दांव से धीरे-धीरे उनके पुराने 'दोस्त' जैसे पीएम मोदी, पुतिन के बाद अब एलन मस्क उनसे दूर हो रहे हैं।

मस्क और ट्रंप के झगड़े के पीछे मोदी की कूटनीति तो नहीं

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप और मस्क के पीछे बढ़ते विवाद का एक कारण भारत भी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान मस्क से मुलाकात कर उन्हें भारत में टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरूकरने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद मस्क भी इस विषय पर काफी एक्टिव हुए और उन्होंने मुंबई में लगभग 24 हजार वर्गफीट जगह पर अपना मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट आरंभ करने का निर्णय मोदी सरकार को भेज दिया है। ऐसे में ट्रंप को इस बात का भय है कि कहीं मोदी अपने कूटनीति से मस्क को उनके विपक्ष में न खड़ा कर दे जिससे आने वाले समय में उन्हें बड़ा नुकसान हो जाये। जाहिर है कि मोदी और बाइडेन की दोस्ती को लेकर दुनिया जानती है और यह भी लोगों को आशंका है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फिलहाल दोस्ती खटास में जाती दिखाई दे रही है।

इसलिये बदलने लगे ट्रंप के तेवर

विशेषज्ञ भी ट्रंप के बदले तेवर और नीतियों को समझने की कोशिश कर रहे। विशेषकों की मानें तो मौजूदा यूएस राष्ट्रपति की विदेश नीति किसी एक विचार से ज्यादा डील्स पर चलती है। उन्हें जहां फायदा दिखता है, वो वहीं चले जाते हैं। भले ही इससे उनका कोई करीबी दोस्त दूर हो जाए। इसका ताजा उदाहरण एलन मस्क के रूप में सबके सामने है। ट्रंप के साथ मस्क का विवाद यूएस प्रेसीडेंट की नई नीति वन बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरूहुआ।

मस्क ने उठा दिए ट्रंप की नीतियों पर सवाल

एलन मस्क ने ट्रंप की नई नीति वन बिग ब्यूटीफेल बिल की आलोचना की। यह बिल टैक्स कटौती को बढ़ाने और अन्य संघीय कार्यक्रमों के लिए फंड बढ़ाने से जुड़ा है। मस्क ने ट्रंप की इस नीति पर सवाल उठाए। इसे अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लिए खराब बताया। इस आलोचना से नाराज होकर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मस्क को पागल तक कह दिया और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी उनकी कंपनियों के साथ सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी दी।

यूएस अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पड़ सकता है असर

ट्रंप ने लिखा कि मैंने एलन की बहुत मदद की, लेकिन अब वह मेरे खिलाफ हो गए हैं। सरकारी अनुबंध खत्म करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। अमेरिकी

राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य वस्तुओं को ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं निलंबित करने की धमकी दे दी। अगर स्पेसएक्स ऐसा करता है तो इससे नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास नासा के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध हैं।

अब मस्क ने फोड़ दिया ट्रंप पर बड़ा बम

एलन मस्क यहीं नहीं रूके उन्होंने यूएस राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है बड़ा बम फोड़ने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्सटीन फाइल्स में है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। एलन मस्क ने एक और पोस्ट में कहा कि इसे भविष्य के लिए मार्क कर लें। सच्चाई सामने आएगी। यही नहीं मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने और उनकी जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग वाली एक पोस्ट को भी शेयर किया।

पीएम मोदी से दोस्ती के बाद ट्रंप ने बदले तेवर

मस्क ही नहीं इससे पहले ट्रंप ने भारत के साथ भी धोखा किया। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छी दोस्ती कई बार देखी गई। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों में दोनों नेता 'दोस्त' की तरह नजर आए। हालांकि, जब ट्रंप को दोस्ती निभाने का मौका मिला, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का साथ दिया। ट्रेड पॉलिसी में भी ट्रंप ने भारत को चुनौती दी। ट्रंप के तेवर भांपते ही केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर लगाया। इसके साथ ही पुराने दोस्त रूस के साथ मेलजोल बढ़ाकर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया।

आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?

एलन मस्क, पीएम मोदी ही नहीं ट्रंप ने खेला रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी किया। पुतिन से दोस्ती के समय उन्होंने जेलेंस्की को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि, पुतिन से नाराजगी के बाद वे जेलेंस्की पर फिर मेहरबान हो गए। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप की विदेश नीति में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। उनकी नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि डील्स पर आधारित होती है। ट्रंप को जहां फायदा दिखता है, वो वहीं चले जाते हैं। लेकिन इससे उनके करीबी दोस्त छिटकते दिख रहे। जैसा कि मस्क के मामले में नजर आ रहा, जिनसे टकराव मोल लेना ट्रंप के लिए तगड़े झटके से कम नजर नहीं आ रहा।

कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, इजराइल और यूक्रेन के बीच षडयंत्र तो नहीं रच रहे

विजया पाठक

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रदर्शन अक्सर देशों की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के केंद्र में रहता है। लेकिन क्या वाकई एक देश को शक्तिशाली साबित करने का एकमात्र तरीका युद्ध, सैन्य प्रदर्शन और टकराव की नीति है? रूस-यूक्रेन, इज़राइल-ईरान, भारत-पाकिस्तान जैसे मौजूदा टकराव न केवल इस सवाल को उठाते हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं। शक्ति प्रदर्शन का अर्थ केवल युद्ध नहीं है। यह किसी देश की सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन है जिससे वह अन्य देशों को प्रभावित या नियंत्रित कर सके। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, अमेरिका अपने सैन्य अड्डों और डॉलर की ताकत के ज़रिए, जबकि भारत डिजिटल डिप्लोमेसी व सॉफ्ट पॉवर के ज़रिए यह काम करता है। लेकिन कई बार यह शक्ति प्रदर्शन सैन्य टकराव में बदल जाता है- जैसे रूस-यूक्रेन, इज़राइल-ईरान, और भारत-पाकिस्तान के मामलों में देखा जा सकता है।

विस्तारवाद बनाम अस्तित्व की लड़ाई

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तीन वर्ष पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण था भू-राजनीतिकरण। यूक्रेन पश्चिमी देशों, विशेषकर नाटो और यूरोपीय संघ के करीब जाना रूस को असहज करता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को ऐतिहासिक रूस का हिस्सा बताया और नाटो विस्तार को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

यही नहीं क्रीमिया और डोनबास को लेकर विवाद गहराया। दरअसल वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण और डोनबास क्षेत्र में रूसी-समर्थक विद्रोहियों का समर्थन इस युद्ध का पूर्व संकेत था। कुल मिलाकर अब तक लाखों लोगों का विस्थापन, वैश्विक उर्जा संकट, खाद्यान्न आपूर्ति में बाधा, यूरोप में अस्थिरता और अमेरिका-रूस टकराव जैसी स्थिति बनती जा रही है।

अस्तित्व की चिंता या वर्चस्व की लड़ाई

इजराइल और ईरान के बीच चल रहा विवाद दशकों पुराना है लेकिन 2020 के बाद से विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इज़राइल के सीरिया व गाजा में हमलों के चलते यह टकराव और बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा कारण है धार्मिक और राजनीतिक वैमनस्य- शिया ईरान और यहूदी इज़राइल के बीच वैचारिक टकराव। इज़राइल को डर है कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सीरिया, लेबनान (हिज़्बुल्लाह), गाजा (हमास) और यमन जैसे मोर्चों पर दोनों देश लगातार एक-दूसरे के खिलाफसक्रिय हैं।

ऐतिहासिक घाव और कश्मीर का प्रश्न

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 07 दशकों से विवाद गहराया हुआ है। वर्ष 1947 के विभाजन के बाद से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। अब तक तीन पूर्ण युद्ध (1947, 1965, 1971) और कारगिल संघर्ष (1999) इसका प्रमाण हैं। अब तक भारत-पाक के बीच में कश्मीर का विषय, सीमा पार आतंकवाद, पानी के बंटवारे जैसे मुद्दे (सिंधु जल संधि), पुलवामा (2019) और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा किये। वर्तमान स्थिति देखी जाये तो भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को पूर्ण रूप से अपना अंग घोषित किया, जिससे पाकिस्तान ने विरोध जताया। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भारत लगातार लगाता रहा है।

शांति के रखवाले या जंग के व्यापारी

अमेरिका, वैश्विक राजनीति में स्वयं को लोकतंत्र और शांति का समर्थक बताता है। लेकिन कई मौकों पर उसकी नीतियां टकराव को बढ़ावा देती नज़र आई हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को भारी सैन्य और वित्तीय सहायता दी। इससे युद्ध लंबा

खिंचा। रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे उर्जा संकट और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा। अमेरिका इज़राइल का प्रमुख सहयोगी है। ईरान परमाणु समझौते से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाहर निकलने से टकराव और बढ़ गया। अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार देना और भारत के आतंरिक मामलों में टिप्पणी कभी-कभी संदेह पैदा करती है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को बढ़ावा दे रहे?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय टकराव या तो तेज़ हुए या उनके समाधान की दिशा में गंभीर कोशिशें नहीं हुईं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान परमाणु समझौता रद्द करना, उत्तर कोरिया के साथ फोटो-ऑप कूटनीति, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं, यूक्रेन को हथियार आपूर्ति के मुद्दे को घरेलू राजनीति (बाइडेन के खिलाफ जाँच) के लिए इस्तेमाल करना। कुल मिलाकर वर्तमान समय में जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं वह यह दर्शाते हैं कि शक्ति प्रदर्शन केवल सैन्य हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीतिक रणनीतियों, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक गठबंधनों से भी संभव है। भारत जैसी उभरती शक्तिने यह दिखाया है कि विकास, विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक नीति में संतुलन बना कर भी विश्व में प्रभाव जमाया जा सकता है। शांति की तलाश और सहयोग की भावना के बिना शक्ति प्रदर्शन विनाश की ओर ही ले जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश रणनीतिक संयम, सार्थक संवाद और बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दें।

अमेरिका इज़राइल का प्रमुख सहयोगी है। ईरान परमाणु समझौते से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाहर निकलने से टकराव और बढ़ गया। अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार देना और भारत के आतंरिक मामलों में टिप्पणी कभी-कभी संदेह पैदा करती है।

ईरान-इजरायल के बीच युद्ध विराम

परमाणु हथियारों के बहाने किए युद्ध का परिणाम

प्रमोद भार्गव

ईरान-इजरायल के बीच 12 दिन चला युद्ध बीच में अमेरिका द्वारा ईरान के एक साथ तीन परमाणु ठिकानों पर हमला, जवाबी कार्यवाही में ईरान का कतर में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर अल-उदैद हमले के आखिरी परिणाम क्या निकला? कहना मुश्किल है। यह युद्ध और इस युद्ध के हासिल नटखट बच्चे की हरकतों की तरह देखने में आए है। ये हरकतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं। इजरायल ने ट्रंप की शह पर ईरान पर मिसाइलों से हमले इसलिए किए, जिससे उसकी परमाणु क्षमता को नष्ट कर अपने देश की रक्षा कर ली जाए। इसी दौरान आ बैल मुझे मार कहावत को चरितार्थ करते हुए अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए। और दावा किया कि इन परमाणु संयंत्रों को इतना नुकसान हो गया है कि अब कई साल तक ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ये बम बनाना तब और मुश्किल हो गया है, जब इजरायल ने ईरान पर किए पहले ही हमले में वहां के अनेक परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था। युद्ध के ग्यारहवें दिन ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। परंतु इस घोषणा के बाद दोनों ही देशों ने एक-दूसरे पर हमले किए। यही नहीं ईरान ने भी अमेरिका के अरब देशों में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया और ट्रंप ने दावा कर दिया कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हो गया है। कतर ने भी इस युद्ध विराम में मध्यस्था के भूमिका अदा की। लेकिन इस युद्ध की जरूरत क्या थी, यह सवाल जस की तस बना हुआ है।

दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो गई है। परंतु पलटवार करते हुए ईरान ने

कहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान बम बनाने से बहुत दूर हो गया है। तब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? परमाणु हथियारों के जानकार कह रहे हैं कि ईरान के पास 20 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता थी, जो अब घटकर 6 बम बनाने की रह गई है। जबकि ट्रंप का घोशित लध्य था कि ईरान यूरेनियम क्षमता बढ़ाने के लिए जिस तेजी से संवर्धन कर रहा है, वह तय सीमा से बाहर की बात होती जा रही है। लेकिन ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता कम भले ही हो गई हो, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह तथ्य तीनों देशों के आए बयानों से सत्यापित होता है। अतएव ईरान पर किया गया बेवजह हमला, कुछ वैसा ही रहा जैसा 2003 में अमेरिकी राश्ट्रपति बुश ने ईराक पर यह कहते हुए किया था कि ईराक के पास बड़ी मात्रा में जैविक हथियार हैं। जबकि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अमेरिका जैविक हथियार होने का कोई प्रमाण दुनिया को नहीं दे पाया। हां, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतारने के बाद तेल के कुओं पर जरू र कब्जा कर लिया। बावजूद यह आशंका बनी हुई है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो बम गिराए हैं, उनसे यदि रिसाव होता है तो एक बड़े भू-क्षेत्र में परमाणु विकिरण का संकट पैदा हो सकता है।

अमेरिका ने ईरान के परमाणु संवर्धन प्रतिष्ठान फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अत्याधुनिक बी-2 घातक बमों से हमला किया था। इन बमों को सटीक निशाने पर दागने के लिए अमेरिकी पनडुब्बियों ने पहले दो मिसाइलों से बम गिराए, जिससे बंकर बस्टर बमों के लिए मैदान साफकिया गया। इसके बाद बम दर्शकों ने आसमान से एक के बाद एक 14 जीबीयू-57 बी बंकर बस्टर दाग दिया। इस पूरे अभियान को नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने 15 युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। उपग्रह द्वारा निर्देशित 2400 किलो परमाणु विस्फोटक साथ ले जाने वाला यह बम जमीन में घूमता हुआ 60 मीटर गहराई तक जाने के बाद विस्फोट करके अपने लक्ष्य साधने में सफल हुआ। अमेरिका ने तीनों ठिकानों पर 14000 किलो विस्फोटक वाले बम गिराए थे, अतएव भविष्य में विकिरण का खतरा पैदा हो सकता है?

अमेरिका ने जिन तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया है, वह सभी ईरान के प्रमुख

यूरेनियम संवर्धन ठिकाने हैं। यहां संयंत्रों में प्राकृतिक यूरेनियम को अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम में बदला जाता है। इसी यूरेनियम को प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। परमाणु बिजली बनाने के लिए 3-5 प्रतिशत का यूरेनियम संवर्धन पर्याप्त होता है, लेकिन हथियार बनाने के लिए यूरेनियम-235 संवर्धन की जरूरत होती है। यह हमले जिस तादाद में किए गए हैं, उससे बड़े पैमाने पर परमाणु विकिरण रिसाव की आशंका जताई जा रही हैं। परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक विस्फोटकों और रसायनों से भिन्न होते हैं। ये बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उर्जा छोड़ते हैं, यह उर्जा अनेक कड़ियों में रसायनिक प्रक्रियाएं आरंभ कर देती हैं। जो व्यापक और दीर्घकालिक क्षति पहुंचा सकती है। परमाणु हथियार कुछ ही पलों में बड़ी मात्रा में उर्जा छोड़ते हैं, जो आसपास के वायुमंडल को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गरम कर देती हैं। इस विस्फोट से अनेक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण फैल जाते हैं, जो अत्यंत घातक होते हैं। हालांकि ईरान के इन ठिकानों में रखे परमाणु हथियारों में विस्फोट की कोई आशंका नहीं है। क्योंकि

विस्फोट के लिए परमाणु उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जो हमलों से संभव नहीं है, लेकिन इनमें रिसाव होता है। ऐसे में रासायनिक और रेडियोलाजिकल रिसाव दोनों ही संकट में डालने वाले होते है। रेडियोलाजिकल रिसाव 1996 में रूस के चेर्नोबिल और 2011 में तूफान आने से जापान के फुकुशिमा में हुआ था। अतएव हमलों के कारण परमाणु विकिरण रिसाव की आशंका बनी हुई है। अतएव कह सकते हैं कि अमेरिका ने परमाणु विकिरण संकट खत्म किया है या बढ़ाया है।

अमेरिका का यह हमला दुनिया के अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने ही देश के कानूनों की परवाह नहीं करता है। इसीलिए अमेरिका के भीतर इस परमाणु हमले को लेकर अमेरिकी जनमत विभाजित दिखाई दे रहा है। दरअसल किसी देश पर हमला करने के लिए ट्रंप को अमेरिकी संसद में हमले का प्रस्ताव लाकर अनुमोदन की जरूरत थी। परंतु उन्होंने इस प्रक्रिया पर अमल नहीं किया। जबकि अमेरिका की ही बात करें तो अप्रैल 2003 में इराक पर हमले के समय बुश ने संसद से मंजूरी ली थी। इसलिए ट्रंप के समर्थकों के साथ विपक्ष भी नाराज है। नाटो देश भी इस युद्ध पर सहमत दिखाई नहीं दिए। रूस और चीन खुले रूप में ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। चूंकि भारत के ईरान और इजरायल दोनों से ही मधुर, कूटनीतिक संबंध हैं, इसलिए तटस्थ रहते हुए शांति की पहल करता रहा।

अंतरराष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरूद्ध अमानुशिक कृत्य मानते हैं। इनके उपयोग के बाद संयुक्त

राश्ट्र सुरक्षा परिशद (यूएनएससी) के कठोर आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जितनी भी अंतरराश्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे सब अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों के दबाव में रहती हैं। यही देश इन संस्थानों को चलाने के लिए धन मुहैया कराते हैं और इन्हीं देशों के लोग इन संस्थानों के सदस्य होते हैं, इसलिए यहां पक्षपात साफ दिखाई देता है। अतएव ईरान में परमाणु विकिरण फैल भी जाए, तब भी अमेरिका के विरूद्ध कोई प्रतिबंध लगाना असंभव है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने तो कह ही दिया था कि यह संघर्ष बड़ा रूप ले सकता है। अतएव संकट का कूटनीतिक हल निकालना जरूरी है। इसलिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना जरूरी है। उसे समझौते के लिए बात करनी चाहिए। बातचीत से कूटनीति हल तो नहीं निकला लेकिन अमेरिका की धमकी ने युद्ध विराम का काम कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सहयोग से 1957 में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 1970 में परमाणु बिजली घर बना लिया था। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को सहयोग करना बंद कर दिया। बावजूद पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बना लेने का आरोप लगाते रहे। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के बाद भी ईरान पर शंकाएं की जाती रहीं। इजरायल ने जासूसी करके कुछ ऐसे सबूत जुटाए जिनसे यूरेनियम संवर्धन की आशंका मजबूत हुई। 2000 में वैश्विक परमाणु निरीक्षकों को नतांज में सवंर्धित यूरेनियम मिला। हालांकि ईरान ने पहले संवर्धन रोक दिया था, लेकिन इजरायल की बढ़ती सामरिक क्षमता के चलते उसने गुपचुप परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इस कारण ईरान पर पश्चिमी देशों ने यह कहते हुए अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे कि ईरान परमाणु बम बनाने के निकट पहुंच गया है। बाद में कई साल चली वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिबंध हटा लिए थे। इस समझौतें में ईरान को असैन्य यूरेनियम संवर्धन को 3.67 प्रतिशत तक रखना मान्य कर लिया था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने समझौते से हाथ खींच लिए और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। 2023 में आईएईए ने कहा कि ईरान में 83.7 प्रतिशत शुद्धता के यूरेनियम कण मिले हैं और उसके पास 128.3 किलो संवर्धित यूरेनियम है। मई 2025 में आईएईए ने दावा किया कि ईरान के पास 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 408 किलो है। इससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते है। इसे ही नष्ट करने के लिए युद्ध और युद्ध विराम का यह खेल खेला गया। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। तब फिर इस युद्ध के परिणाम क्या निकले।

Laxman Yadav: 'Manusmriti' could only be taught alongside 'Gulamgiri' and 'Annihilation of Caste'

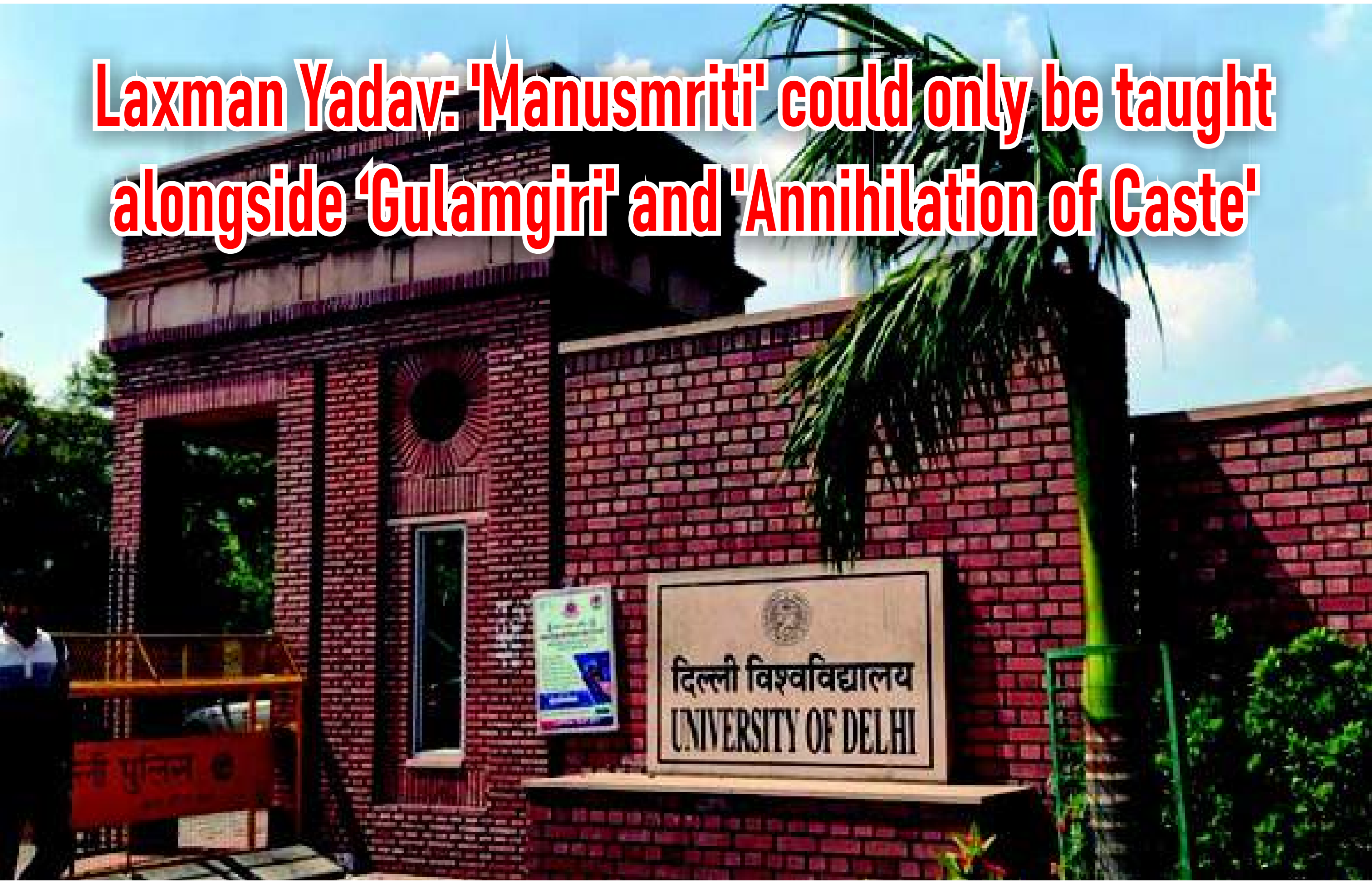

Nawal Kishore Kumar

Recently, Delhi University Vice-Chancellor Yogesh Singh announced that Manusmriti would not be part of the syllabus of any academic programme of the University. The announcement came in the wake of the university's Sanskrit department trying to include the text in its syllabus. Prof Laxman Yadav, Bahujan thinker and author of the bestseller 'Professor Ki Diary' (A Professor's Diary), who taught in the university for 14 years, spoke with the issue.

The vice-chancellor of Delhi University has announced that Manusmriti will not be part of the syllabus of any academic programme of the university. It is believed that the announcement followed fierce opposition to the move. Should the teaching of Manusmriti be opposed?

To begin with, Manusmriti is a book that was burnt by Babasaheb Ambedkar. That was about a century ago. Please note that Baba Saheb did not burn any other book. He did critique other Hindu scriptures but didn't burn them. He burnt Manusmriti because it was not even worth critiquing. The Manusmriti advocates depriving Dalits, Shudras and women of many rights. It justifies denial of education to them as well as discrimination against them while dispensing justice. That is why the text is rejected. Attempts were made to include it in the curriculum in Delhi University. One argument is that teaching such texts would lend them legitimacy. We have to reject Manusmriti; we don't have to study it. There is nothing worth studying in it. This is one way of looking at the issue. Clearly, from this perspective, Manusmriti should not be included in the DU syllabus. The other argument is that if it is not taught in universities, where will it be taught? My view is that if you believe that Manusmriti should

be taught in universities then the next chapter after Manusmriti should be Gulamgiri, followed by Annihilation of Caste. If you want to teach Manusmriti thus, please go ahead.

Manusmriti was first sought to be inserted in the history syllabus and next in a course on law. The vice-chancellor says that a year ago he had issued instructions that Manusmriti should not be included in any syllabus. Now, the Sanskrit Department was caught trying to include it. Don't DU departments follow the orders of the VC?

Of course, all departments should adhere to the instructions of the VC. If once the VC has directed that Manusmriti should not be included in any academic programme, then it should not be. But as your question suggests, this did not happen. Despite clear instructions, a department tried to include the book in the syllabus. This means that rules are being flouted in DU. However, my take on this issue is that people with an RSS [Rashtriya Swayamsevak Sangh] mindset do not accept the Constitution. They want to build Manusmriti's India. This mindset was exposed when the RSS began opposing the Constitution just three days after its adoption by the Constituent Assembly on 26 November 1949. They said that the Constitution hasn't adopted anything from the Manusmriti. RSS still doesn't consider the Constitution as its own. Sometimes, they contest elections with the motive of changing the Constitution. At other times, they make “great men” demand that a new Constitution be enforced. This is the mindset of the VC, too. So, this might have been a trial balloon. Let us see what reaction the introduction of Manusmriti elicits. Will it be opposed? Can we push it through the backdoor?

The Vedas, Upanishads, Puranas as well as other texts like the Ramayana and the Mahabharata also uphold discrimination based on caste, varna and gender. But there are no restrictions vis-à-vis these texts. Even Kautilya's Arthashastra seems acceptable. Could maintaining this stance on Manusmriti be a stratagem to lend acceptability and legitimacy to these other texts?

You are right. But you see, there are some things which have nothing worth critiquing, nothing worth responding to. Manusmriti is one of them. It combines an inhuman mindset with an exhaustive list of injustices. It lends legitimacy to inhumanity and injustice. It is not just another text. Nowhere do the Ramayana, the Mahabharata or Kautilya's Arthashastra prescribe

how a society should be. If a Shudra sits beside a Brahmin, his buttocks should be severed neither Mahabharata nor Ramayana or any other scripture says things like this. But Manusmriti does. Manusmriti says women should not have the right to education and they should always be subservient to their fathers, husbands and sons. A Shudra can be sentenced to death for a crime. But if a Brahmin commits the same crime, he can be pardoned. No other scripture makes such prescriptions. So, Manusmriti should be rejected at all costs.

One question that begs an answer is that if our people won't read Manusmriti, they won't know what it says. And if they don't know what it says, how will they oppose it?

As a professor who has taught for 14 years, my answer to this question would be the same as that to your first question. If a university wants to teach Manusmriti or feels that it should be taught, then books that counter it should also be taught. Or is it that you want to teach only Manusmriti? You have already appointed RSS people as VCs of all universities. Most of the professors are also of the same mindset. Shakhas are being held in universities. This shows what direction you want higher education to take. Let me give you an example. This could be taken as a challenge, too. Let the university hold a seminar on the topic that this country will be run as per the Constitution and not the Manusmriti. Not one DU professor will agree to organize a seminar on this topic. Universities are now controlled by the RSS and if the universities want to teach Manusmriti, their objective surely is not making Dalits and the Backward Classes aware.

Tell us something about how DU makes its syllabuses? What is the process, the mechanism? Has it changed in recent years?

The changes have not come about overnight. I have written a book, Professor Ki Diary. I won't go into the details here but in my book, I talked about issues like what universities are meant for, what is their importance, what should happen there and how. In short, I would like to say that as far as higher education goes, there never was a golden period for the Dalitbahujan. The demography of universities began changing slowly after the Constitution came into force and the reservation system kicked in. With a [reserved seats] roster system in place, the first generation of Dalits and the Backward Classes began entering the portals of universities. The process of democratization commenced. But the handful of people from the dominant classes know very well that if Dalit-OBCs

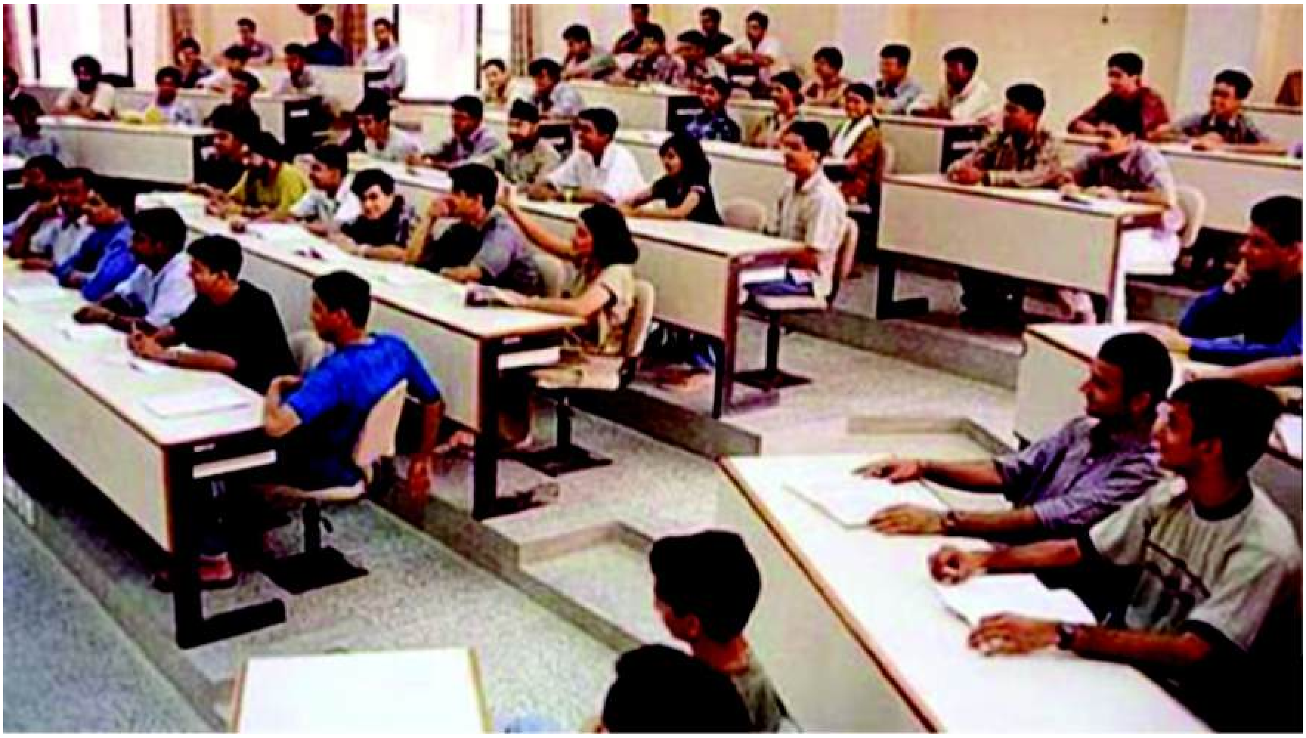

enter universities in large numbers, if they manage to enter the administrative set-up of the varsities, then they would start answering them back and a counter-narrative would start building. That is why they have been consistently conspiring to block the entry of Dalit-OBCs into universities. This has been happening for a long time and it is continuing. Provision for lateral entry, the ploy of not-found-suitable [NFS] candidates and appointing professors on contractual basis they are using all these methods to serve their own ends. Nowadays, guest professors are being appointed in large numbers. Then, there is exploitation and persecution within institutions Rohith Vemula is a case in point. There are some kinds of exploitation that are invisible to others but Dalit and OBC professors and students have to put up with exploitation and deprivations on a daily basis. The situation has worsened over the past 10 years. That is because the RSS has realized that controlling centres that impart knowledge can perpetuate its rule.

The situation today is that even if the BJP loses the next election, teachers wedded to the RSS ideology will continue teaching students for the next 30 years. There has been a sea change in universities over the past 10 years. I can say with some degree of confidence that there is not a single VC today who doesn't profess the RSS ideology. Of course, there may be some professors who don't subscribe to the RSS ideology. All kinds of corruption are happening in universities. It is not that there were no RSS men in universities earlier. But there were socialists, Congressmen and communists, too. They used to discuss things, had debates. But over the past 10 years, universities have become an exclusive preserve of the Sanghis. If you hold views opposite to theirs, they won't even talk with you. The New Education Policy has ruined the education system in universities. The changes that have come about over the past 10 years are very dangerous.

The dominant sections of society are trying to get Manusmriti included in the syllabuses. Why can't the Dalitbahujan make an attempt to get the writings of Phule, Periyar and Ambedkar included in the syllabuses? Why can't they launch such a movement?

Please note the Uttar Pradesh government has decided to merge schools. Most of the students in these schools are Dalitbahujan. They must be 99 per cent and others one per cent. The Dalitbahujan have been unable to stop closure of their schools, they are not able to stop the fee hikes in their schools, and they are not able to stop the communalization of school syllabuses. Then, how can you expect that they will launch a movement? The poor Dalitbahujan won't do it. It has to be done by the educated among them. The Dalitbahujan professors can't organize even a seminar on their worldview in the universities. They just want to protect their jobs. They fear that if they speak up, their promotion may be jeopardized. How can you expect a community that is keeping mum on the most basic issues to think about the deeper issues, to launch a movement on what should be part of the syllabus and what should be removed from it.

My answer is that I am disappointed with my community. I am dejected. When a community is unable to fight on major, very obvious issues, I don't think it is ready for a battle on deeper issues. Of course, I want that battles should be launched on all issues, at all levels. They should fight against the commercialization of education, against appointment of RSS acolytes as professors, against the domination of the RSS. They should have their say on every issue, including the syllabus of universities.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

औद्योगिक नीति
अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक
और उद्यमों के लिए लाभकारी
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
स्थानीय युवाओं को
रोजगार देने वाले उद्योगों
को विशेष अनुदान
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर,
रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर
को विशेष पैकेज
आधुनिक खेती से लेकर
खिलौना उद्योग तक को
मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन और होटल
व्यवसाय को बढ़ावा
वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर
अब 200 फीसदी तक
का प्रोत्साहन
नीति में संशोधन से युवाओं,
किसानों, उद्यमियों और
निवेशकों को सीधा लाभ
RO. No. 13282/2
QR स्कैन करें
विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़
Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ में
नई औद्योगिक क्रांति
• स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज
• आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा
• पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा
• वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर अब 200% तक का प्रोत्साहन
RO. No. 13317/1
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in